

ifronu fnukad 10 tuojh 2019 dks  
fo/kkul Hkk dsi Vy ij i Lrqr fd; k x; k



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र  
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-5

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र  
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या—5

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
<b>अध्याय-1</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.3	2
लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया	1.4	2
पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	1.5	3
कपटपूर्ण आहरण एवं लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर वसूलियाँ	1.6	4
<b>अध्याय-2</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>जनजातीय कार्य विभाग</b>		
अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा	2.1	7
<b>लेखापरीक्षा कंडिकाएं</b>		
<b>जनजातीय कार्य विभाग</b>		
बैंक खाते का अनाधिकृत संचालन एवं ब्याज की हानि	2.2	26
<b>नगरीय विकास एवं आवास विभाग</b>		
निरर्थक व्यय	2.3	28

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1.1	चयनित जिले, विकासखण्ड एवं आवासीय विद्यालय/छात्रावास	31
2.1.2	ई.एम.आर.एस. में स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति	33
2.1.3	नमूना जांच किये गये ई.एम.आर.एस. में जिला स्तरीय समितियों की बैठकें	34
2.1.4	मध्य प्रदेश क्रय नियम के अनुपालन बिना किए गए क्रय	35

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों के लिये एक विहंगावलोकन एवं दो अध्यायों में संरचित है। अध्याय-1, लेखापरीक्षित इकाईयों के संबंध में सामान्य जानकारी, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शासन की प्रतिक्रिया तथा कपटपूर्ण आहरणों एवं लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली के प्रकरणों का वर्णन करता है। अध्याय-2 में एक अनुपालन लेखापरीक्षा 'अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा' तथा दो लेखापरीक्षा कड़िकायें शामिल हैं। महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे उल्लेखानुसार थीं:

### अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन पर ₹ 2,686.12 करोड़ का व्यय किया। हालांकि, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में बुनियादी ढांचे में कमी थी जैसे कि कर्मचारियों के साथ रहवासियों के लिए अपर्याप्त आवास, चारपाई, भोजन के लिए जगह, शौचालय, अपूर्ण निर्माण कार्य इत्यादि। जनजातीय कार्य विभाग ने 247 प्री-मैट्रिक छात्रावासों में आवासीय क्षमता में वास्तविक वृद्धि किये बिना सीट वृद्धि की। आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई। कलेक्टर रहवासियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

आयुक्त, आदिवासी विकास ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 113.84 करोड़ के अवास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे। प्रावधान का उल्लंघन कर क्रय किये जाने के अलावा, लेखापरीक्षा ने ₹ 6.03 करोड़ के न पता लगाये जा सके अग्रिम भी देखे जो आठ से 15 वर्ष पूर्व कलेक्टरों को जारी किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2016-17 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

---

---

विहंगावलोकन

---

---

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभागों की अवधि 2016-17 के दौरान की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष के परिणाम सम्मिलित हैं। यह प्रतिवेदन दो अध्यायों में संरचित है। अध्याय-1, लेखापरीक्षित इकाईयों के संबंध में सामान्य जानकारी, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शासन की प्रतिक्रिया तथा कपटपूर्ण आहरणों एवं लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली के प्रकरणों की जानकारी प्रदान करता है। अध्याय-2 में एक अनुपालन लेखापरीक्षा 'अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा' एवं दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं। प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की कुल मनी वैल्यू ₹ 147.44 करोड़ है जिनमें व्यवस्थागत खामियाँ, अनियमित व्यय, निरर्थक व्यय, कपटपूर्ण आहरण आदि से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिये निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। लेखापरीक्षा के नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धति के आधार पर निकाले गये हैं। अपनाई गयी विशिष्ट लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली का उल्लेख अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका में किया गया है। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये तैयार किये गये हैं तथा अनुशंसायें की गई हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में दिया गया है।

### 1. अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश में, 20 जिलों में 89 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड हैं। राज्य शासन ने अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के लिए 1,051 आश्रम शाला (कक्षा एक से आठ के लिए), 78 कन्या शिक्षा परिसर (कन्याओं हेतु कक्षा छह से 12 के लिए आवासीय विद्यालय), 1,368 प्री-मैट्रिक छात्रावास और 210 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास स्थापित किये हैं। केन्द्रीय क्षेत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) योजना के अन्तर्गत, एस.टी. श्रेणी के छात्रों को कक्षा छह से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने के लिए राज्य में 29 ई.एम.आर.एस. की स्थापना की गयी है।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, राज्य शासन ने एस.टी. के लिए इन आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन पर ₹ 2,686.12 करोड़ का व्यय किया था, जिसमें आश्रम शालाओं और छात्रावासों के निर्माण के लिए ₹ 71.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता और ई.एम.आर.एस. के संचालन के लिए ₹ 244.66 करोड़ का सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) शामिल था।

आदिवासी विकासखण्डों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक के बच्चों की शिक्षा के लिए जनजातीय कार्य विभाग उत्तरदायी है। एमपी ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इन्सटीट्यूट्स सोसायटी (सोसायटी) को ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन के लिए; आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा अधिकृत किया गया था। 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के लिए राज्य में एस.टी. हेतु आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:-

## ई.एम.आर.एस. का वित्तीय प्रबंधन

सोसायटी ने रोकड़ बही का उचित संधारण नहीं किया और अन्य संबंधित अभिलेख जैसे कि लेजर, बैंक मिलान पत्रक भी तैयार नहीं किये। सोसायटी के वार्षिक लेखे जिन्हें वित्तीय वर्ष पूरा होने के 90 दिनों के भीतर तैयार किया जाना था, 2015-16 और 2016-17 के लिए तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि सोसायटी सनदी लेखाकार (सी.ए.) को नियुक्त करने में विफल रही। आवश्यक अभिलेखों की अनुपस्थिति संभावित दुरुपयोग और धोखाधड़ी के खतरे का सूचक है।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के अनिवार्य बही-खातों को संधारित करने और खातों को अंतिम रूप देने में विफलता की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विफलता जानबूझकर नहीं थी तथा दुरुपयोग और धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं थी, सतर्कता दृष्टिकोण से करनी चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को इस विफलता के लिए सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए तथा अविलंब उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए।

2012-13 से 2016-17 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 282.19 करोड़ के जी.आई.ए. के लिए सोसायटी द्वारा भेजे गए उपयोगिता प्रमाणपत्र की जांच से पता चला कि उपयोगिता प्रमाणपत्र अवास्तविक थे, क्योंकि मार्च 2017 की स्थिति में सोसायटी के ई.एम.आर.एस. बैंक खातों में ₹ 113.84 करोड़ (ब्याज सहित) की अप्रयुक्त शेष राशि थी। ₹ 113.84 करोड़ के अवास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए आयुक्त, आदिवासी विकास जिम्मेदार थे।

### अनुशंसा

भारत सरकार को अवास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय करना चाहिए तथा उचित विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए।

आठ से 15 वर्ष पूर्व 18 जिला कलेक्टरों को जारी ₹ 30.69 करोड़ के अग्रिम अगस्त 2018 तक असमायोजित बने रहे। नमूना जांच किये गये तीन जिलों (धार, मंडला और शहडोल) में ₹ 6.03 करोड़ के अग्रिम के अभिलेख नहीं पाये गये।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को सतर्कता दृष्टिकोण से लंबी अवधि से असमायोजित रहे अग्रिम की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दुरुपयोग या धोखाधड़ी नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग और मध्य प्रदेश शासन को अप्रयुक्त अग्रिमों को वापस करने/समायोजित करने में हुई विफलता के लिए जिला और सोसायटी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए। आयुक्त, आदिवासी विकास, जो सोसायटी के पदेन सचिव भी हैं, को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले बकाया अग्रिमों के समायोजन के लिए आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

(कंडिका 2.1.3)

## ई.एम.आर.एस. में शिक्षा की गुणवत्ता

ई.एम.आर.एस. में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी जिसने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ई.एम.आर.एस. के कक्षा 12वीं का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत



ई.एम.आर.एस. के 10वीं कक्षा के सम्पूर्ण उत्तीर्ण प्रतिशत से एवं सी.बी.एस.ई. के अजमेर क्षेत्र के औसत उत्तीर्ण प्रतिशत से अत्यंत कम था। ई.एम.आर.एस में परिणामों की स्थिति चिंता का विषय है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि ई.एम.आर.एस. के छात्रों के प्रवेश के लिए कठोर चयन प्रक्रिया है और इन विद्यालयों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और अन्य वित्तीय सहायता प्रदाय की जाती है जो अन्यथा अन्य शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, शिक्षकों की भर्ती में जनजातीय कार्य विभाग की विफलता के कारण राज्य में एस.टी. के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय के रूप में ई.एम.आर.एस. स्थापित करने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को ई.एम.आर.एस. में प्राचार्यों/व्याख्याताओं/शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिये और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संविदा/अतिथि शिक्षकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

(कंडिका 2.1.4.1)

### बिना योजना के छात्रावासों का उन्नयन करना

जनजातीय कार्य विभाग ने एस.टी. के लिए 330 प्री-मैट्रिक छात्रावासों को, इन छात्रावासों की आवासीय क्षमता में वास्तविक वृद्धि किए बिना 50 सीटर छात्रावास में उन्नयित (दिसम्बर 2012) कर दिया। स्वयं के भवनों में संचालित 318 उन्नयित छात्रावासों में से केवल 71 उन्नयित छात्रावासों में ही नए भवनों/अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया। परिणामस्वरूप, 247 छात्रावासों के रहवासियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक चारपाई दो छात्रों द्वारा साझा किया जा रहा था, शौचालयों और स्नानागारों की कमी इत्यादि।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को 247 छात्रावासों, जो दिसम्बर 2012 में उन्नयित किए गये थे, में तत्काल आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

(कंडिका 2.1.6.1)

### आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में बुनियादी ढांचे/सुविधाओं की कमी

नमूना जांच किये गये 53 (25 बालक और 28 कन्या) आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे की कमी थी, जैसे कि रहवासियों एवं कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त आवास, चारपाई, शौचालय, भोजन की जगह, खेल सामग्री, पुस्तकालय आदि। पालक समिति जो मूल सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है, की बैठकों में अत्यधिक कमी थी।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को प्रत्येक आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पालक समितियों का गठन और वे प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, को सुनिश्चित करना चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त सुविधाएं हैं।

(कंडिका 2.1.6.5)

## रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण

लेखापरीक्षा ने रहवासियों के लिए निर्धारित मासिक स्वास्थ्य परीक्षण में 87 प्रतिशत की कमी देखी। निधि के आवंटन के बावजूद, नमूना जांच किये गये जिलों (धार, खरगौन तथा शहडोल) ने सिकल सेल एनिमिया (एस.सी.ए.) परीक्षण हेतु शिविर का आयोजन नहीं किया। जिला मण्डला ने ₹ 53.55 लाख की पूरी आवंटित निधि का उपयोग किया, जबकि 19 नमूना जांच किये गये आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 10 में एस.सी.ए. परीक्षण आयोजित नहीं किए गए। एस.सी.ए. की स्थिति दर्शाते हुए कोई स्वास्थ्य कार्ड उन नौ आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में भी जारी नहीं किए गए थे जहां परीक्षण आयोजित किए गये थे, जिससे ₹ 53.55 लाख का पूरा व्यय निष्फल रहा।

## अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग रहवासियों के मासिक स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित न होने के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकता है। जनजातीय कार्य विभाग शिविर आयोजित न करने के लिए और जहाँ शिविर आयोजित किए गये हैं वहाँ छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति दर्शाने वाला कार्ड जारी न किए जाने के लिए सम्बन्धित ए.सी.टी.डी./स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर सकता है।

(कंडिका 2.1.8)

## 2. लेखापरीक्षा कंडिकाएं

### बैंक खाते का अनाधिकृत संचालन एवं ब्याज की हानि

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (स.आ.आदि.वि.), सिवनी ने अनाधिकृत रूप से बचत बैंक खाता खोला और बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए आदिवासी कल्याण योजना निधियों की राशि ₹ 112.51 करोड़ जमा किया। स.आ.आदि.वि., जमा धन पर ब्याज के क्रेडिट के लिए बैंक के साथ समय पर कार्रवाई करने में भी असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.44 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.2)

### निरर्थक व्यय

कोयला धारित क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुमति देने से पूर्व, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) की आपत्ति को संज्ञान में लेने में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सिंगरौली विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप कॉलोनी के विकास पर सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 1.95 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ क्योंकि बाद में भूमि को एन.सी.एल. द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

(कंडिका 2.3)

---

---

अध्याय–1  
प्रस्तावना

---

---

## अध्याय-1

### प्रस्तावना

#### 1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के अधिदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों की वर्ष 2016-17 की अवधि में की गई अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य कार्यकारी उत्तदायित्व सुनिश्चित करने और विभिन्न विभागों के प्रशासन की प्रक्रिया और लोक सेवा प्रदाय में सुधार करने में सहायता करना है।

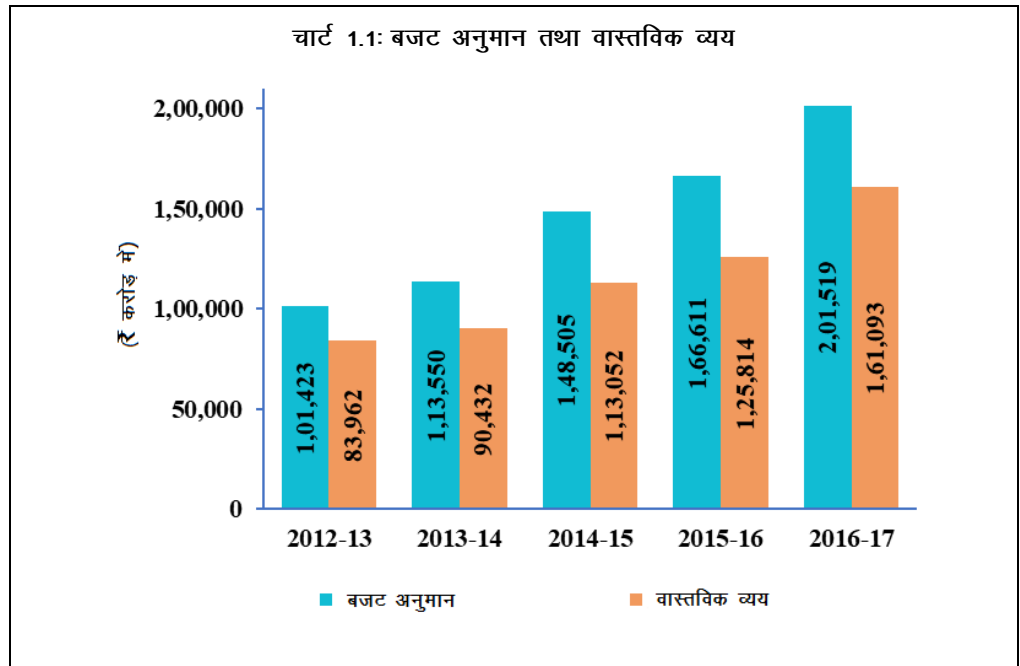
प्रतिवेदन का अभिन्यास निम्नानुसार है:

- 1. अध्याय-1:** लेखापरीक्षित इकाईयों के बारे में सामान्य जानकारी।
- 2. अध्याय-2:** 'अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा' पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं।

#### 1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

मध्य प्रदेश में 54 विभागों में से 35 विभाग सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों द्वारा किया जाता है, जिनकी आयुक्त/संचालक और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है।

वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में वर्णित है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पाँच मुख्य विभागों के व्यय की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दी गयी है:

तालिका 1.1: सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य विभागों का व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	2014-15	2015-16	2016-17
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	13,209.15	16,138.28	27,063.69
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	6,277.98	9,623.91	11,087.57
स्कूल शिक्षा विभाग	7,417.48	7,229.04	9,720.38
वित्त विभाग	7,315.71	8,005.35	8,973.52
गृह विभाग	3,938.13	4,663.00	5,285.18

(स्रोत: संबंधित वर्षों के मासिक विनियोग लेखों से संकलित)

### 1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

वर्ष 2016-17 के दौरान, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश द्वारा सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 35 विभागों की कुल 3,934 लेखापरीक्षित इकाईयों में से 1,369 लेखापरीक्षित इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

### 1.4 लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके अभिमत प्राप्त करने के लिए चार चरण में अवसर प्रदान करता है, जैसे:

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन:** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान उत्तर देने हेतु जारी।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन :** लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अंदर उत्तर देने हेतु जारी।
- **प्रारूप कंडिकाएं:** शासन/विभागीय प्रमुखों जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयाँ कार्य करती हैं, को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के पूर्व शासन/विभाग के विचारों को छः सप्ताह के भीतर भेजने हेतु जारी।
- **निर्गम सम्मेलन:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभागीय/शासन के विचार प्राप्त करने के लिए विभाग के प्रमुख तथा राज्य शासन को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभाग के प्रमुख/शासन को खण्डन करने एवं स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है और केवल जब विभाग के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या समाधानकारक नहीं हैं तो लेखापरीक्षा प्रेक्षण, जैसा भी प्रकरण हो, निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि, ज्यादातर प्रकरणों में, लेखापरीक्षित इकाईयाँ/विभाग, समय पर तथा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

### 1.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन

34 विभागों से संबंधित 4,110 आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को मार्च 2017 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2018 की स्थिति में 9,439 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 27,956 कंडिकाएं ठोस उत्तर की प्रत्याशा में निराकरण के लिए बकाया थीं। इनमें से, डी.डी.ओ. द्वारा, 7,872 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 21,162 कंडिकाओं के प्रारंभिक उत्तर दिये गये थे जबकि 1,567 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 6,794 कंडिकाओं (मनी वैल्यू ₹ 24,155 करोड़) के संबंध में डी.डी.ओ. की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति तालिका 1.2 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.2: 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएं (31 मार्च 2017 तक जारी)

अवधि	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	बकाया कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	डी.डी.ओ. के प्रारंभिक उत्तर हेतु लंबित कंडिकाओं से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	बकाया कंडिकाएं, जिन पर डी.डी.ओ. के प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुए की संख्या (प्रतिशत)	डी.डी.ओ. के प्रारंभिक उत्तर हेतु बकाया कंडिकाओं की मनी वैल्यू (₹ लाख में)
2016-17	1,333 (14.12)	6,888 (24.64)	746 (47.61)	4,028 (59.29)	14,90,008.098
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	1,739 (18.42)	6,600 (23.60)	334 (21.31)	1,314 (19.34)	4,79,428.69
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	1,140 (12.08)	3,611 (12.92)	154 (09.83)	601 (08.85)	2,44,939.31
5 वर्षों से अधिक	5,227 (55.38)	10,857(38.84)	333 (21.25)	851 (12.52)	2,01,080.91
<b>योग</b>	<b>9,439</b>	<b>27,956</b>	<b>1,567</b>	<b>6,794</b>	<b>24,15,457.008</b>

2016-17 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की 18 बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) हुईं जिनमें 994 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 5,523 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

### 1.5 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्रवाई की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जाँच की जा रही हो अथवा नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा सम्पादित विस्तृत कार्यान्वयन टीप भी, जिसमें उनके द्वारा की जा रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाहियाँ दर्शाते हुये प्रस्तुत करनी थी।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 140 लेखापरीक्षा कंडिकाएं प्रतिवेदित की गयी थीं। इनमें से लोक लेखा समिति ने 45 कंडिकाएं मौखिक चर्चा हेतु एवं 95 कंडिकाएं लिखित उत्तर हेतु चयनित की। मार्च 2018 की स्थिति में लोक लेखा समिति की पांच अनुशंसाओं में से शासन से चार अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन टीप प्राप्त हुई, जैसा कि तालिका 1.3 में दिया गया है।

**तालिका 1.3: लोक लेखा समिति में चर्चा की स्थिति, मध्य प्रदेश, विधान सभा**

स्थिति	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 से 2015-16
लेखापरीक्षा कंडिकाओं की कुल संख्या	140
लोक लेखा समिति में चर्चा (मौखिक चर्चा) के लिए चयनित	45
लोक लेखा समिति में लिखित उत्तर के लिए चयनित	95
लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशें	05 (मौखिक चर्चा के अंतर्गत 03 <sup>1</sup> कंडिकाएं+लिखित उत्तर के लिए 2 कंडिकाएं)
कार्यान्वयन टीप प्राप्त	03 (मौखिक चर्चा के अंतर्गत 01 कंडिका+लिखित उत्तर के लिए 2 कंडिकाएं)
विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	03 (मौखिक चर्चा के अंतर्गत 01 कंडिका+लिखित उत्तर के लिए 2 कंडिकाएं)

**1.6 कपटपूर्ण आहरण एवं लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर वसूलियाँ**

**1.6.1 लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.), संधारण संभाग क्रमांक 2, इंदौर के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2016 से दिसम्बर 2016 के बीच दस महीनों के दौरान दो अस्थायी कार्य-भारित कर्मचारियों श्री रमाकांत शर्मा, हेल्पर और श्री गोविन्द रामभाऊ सावंग, टेलीफोन परिचारक के वेतन डेटा को केंद्रीकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्ट करते समय श्री सुनील भोंडवे, सहायक द्वारा बढ़ा दिया गया था जिसे श्री सुनील भोंडवे, सहायक एवं श्री अनिल तिवारी, कार्य-भारित कर्मचारी द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.19 लाख का कपटपूर्ण आहरण हुआ जैसा कि तालिका 1.4 में वर्णित है।

**तालिका 1.4: वेतन का कपटपूर्ण अधिक आहरण**

(₹ में)

नाम (श्री)	देय वेतन	आहरित वेतन	कपटपूर्वक अधिक भुगतान की गई राशि
रमाकांत शर्मा	1,80,409	6,90,411	5,10,002
गोविंद रामभाऊ सावंग	1,72,409	6,81,211	5,08,802
योग	3,52,818	13,71,622	10,18,804

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (नवम्बर 2017) कि संबंधित कर्मचारियों से वसूली हो चुकी थी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जा चुके थे एवं इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए अधीक्षण यंत्री, इंदौर को भी निर्देशित किया गया था।

<sup>1</sup> मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित एक कंडिका पर लोक लेखा समिति द्वारा कोई अग्रतर सिफारिश जारी नहीं की गई।

### 1.6.2 वित्त विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल, मोचा, मंडला (प्राचार्य) के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि प्राचार्य ने तीन अतिथि शिक्षकों के दिसम्बर 2014 से अप्रैल 2015<sup>2</sup> तक की अवधि के राशि ₹ 47,250 का वेतन देयक कार्यालय उप कोषालय (एस.टी.ओ.), नैनपुर को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था। तथापि लेखापरीक्षा की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय उप कोषालय ने राशि में परिवर्तन कर राशि ₹ 97,250 का देयक पारित (26 सितम्बर 2015) किया और राशि ₹ 50,000 एक अन्य अतिथि शिक्षक के नाम पर भुगतान दर्ज किया जो कि इस लेनदेन की जानकारी से इंकार कर चुका है। इसके स्थान पर, राशि ₹ 50,000 की अतिरिक्त राशि, वास्तव में एक अन्य व्यक्ति, श्री अनिल पटले<sup>3</sup> को अंतरित की गई थी, जिनके बारे में किसी भी जानकारी से दोनों ही कार्यालयों<sup>4</sup> ने इंकार किया। लेखापरीक्षा आपत्ति की प्रतिक्रिया में खण्ड विकास अधिकारी बिछिया, (मंडला) ने कहा कि प्राचार्य (डी.डी.ओ.) का पासवर्ड कार्यालय उप-कोषालय, में कार्यरत लिपिक (श्री प्रकाश मरावी) के पास था, जो भुगतान हेतु देयक की सॉफ्ट कॉपी तैयार करता था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि राशि ₹ 50,000 चालान द्वारा शासकीय खाते में जमा कर दी गई थी एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी। तथापि, विभागीय उत्तर इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि आपराधिक अभियोग की एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है।

प्रकरण को वित्त विभाग को भी सूचित (अक्टूबर 2017) किया गया; उनका उत्तर अभी तक (अगस्त 2018) प्रतीक्षित है।

### 1.6.3 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (ए.डी., बी.सी. एम.डब्ल्यू.), बुरहानपुर दिसम्बर 2013 तक एक किराए के मकान में संचालित था। यद्यपि, कार्यालय जनवरी 2014 से पूर्व में एक नई शासकीय भवन में स्थानान्तरित हो चुका था, ए.डी., बी.सी.एम.डब्ल्यू., ने कार्यालय परिसर के किराये के लिए अवधि जनवरी 2014 से अगस्त 2014 तक राशि ₹ 76,000 का आहरण किया। उक्त राशि ई-पेमेंट के माध्यम से उसी कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री परमानन्द बारी के खाते में अंतरित की गयी थी। आगे संवीक्षा में पाया गया कि एक जाली भवन किराया पत्रक (मकान मालिक का माँग पत्र) प्रमाणक के साथ संलग्न किया गया था। उक्त गबन को लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किये जाने पर ए.डी., बी.सी.एम.डब्ल्यू. द्वारा (जून 2017) राशि ₹ 76,000 शासकीय खाते में जमा की गई। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने उत्तर (अगस्त 2017) दिया कि प्रकरण की जाँच की गयी एवं तत्कालीन लेखापाल और ए.डी., बी.सी.एम.डब्ल्यू. को वित्तीय अनियमितता का प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई एवं विभागीय कार्रवाई की जावेगी। प्रकरण दर्ज करने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रगति अपेक्षित है (अगस्त 2018)।

<sup>2</sup> सितम्बर 2015 में प्रस्तुत किया

<sup>3</sup> खाता संख्या 32540633190

<sup>4</sup> प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल, मोचा, मण्डला एवं उप कोषालय, नैनपुर, मण्डला



---

---

## अध्याय–2

### अनुपालन लेखापरीक्षा

---

---

- अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा कंडिकाएं

## अध्याय-2

### अनुपालन लेखापरीक्षा

#### जनजातीय कार्य विभाग

### 2.1 अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा

#### 2.1.1 प्रस्तावना

भारत का संविधान समाज के वंचित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समान अवसर प्रदान करने के साथ उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। मध्य प्रदेश में, 20 जिलों में 89 विकासखण्ड, आदिवासी विकासखण्ड हैं। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के बीच साक्षरता दर 2001 में 41.2 प्रतिशत से बढ़कर 2011<sup>1</sup> में 50.6 प्रतिशत हो गई। हालांकि, राज्य में कुल साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत की तुलना में एस.टी. की साक्षरता दर में 18.7 प्रतिशत का अंतर था। एस.टी. की कम साक्षरता को ध्यान में रखते हुये, राज्य में एस.टी. के लिए निम्नलिखित आवासीय विद्यालय और छात्रावास स्थापित किए गये हैं:-

- *आश्रम शालाएं* : ये आवासीय विद्यालय कक्षा एक से आठ तक के आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। राज्य में, मार्च 2017 तक 1,051 आश्रम शालाएं संचालित थीं, जिनमें से, 242 आश्रम शाला भवनों का निर्माण केन्द्र प्रवर्तित योजना<sup>2</sup> के तहत किया गया था।
- *कन्या शिक्षा परिसर* (के.एस.पी.): वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, कम महिला साक्षरता दर वाले आदिवासी विकासखण्डों में कक्षा छह से 12 तक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य शासन ने कन्याओं के आवासीय विद्यालयों के रूप में 78 के.एस.पी. स्थापित किए।
- राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के साथ केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत *एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय* (ई.एम.आर.एस.) स्थापित किये गये हैं।
- दूरस्थ क्षेत्रों से एस.टी. श्रेणी के छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास स्थापित किए गए हैं। राज्य में संचालित 1,368 प्री-मैट्रिक छात्रावासों तथा 210 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों (मार्च 2017 तक) में से 255 प्री-मैट्रिक छात्रावासों तथा 28 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों का निर्माण भारत सरकार की वित्तीय सहायता<sup>3</sup> से हुआ था।

<sup>1</sup> जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में अनुसूचित जनजाति की सांख्यिकीय रूपरेखा 2013।

<sup>2</sup> केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता में आश्रम शालाओं की स्थापना में कन्या आश्रम शालाओं के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत और बालक आश्रम शालाओं के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था।

<sup>3</sup> अनुसूचित जनजाति कन्याओं और बालकों के छात्रावास हेतु, केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत कन्या छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत और बालक छात्रावासों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था।

- मार्च 2017 तक, 76 आवासीय विद्यालय/छात्रावास भी 35 अशासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) द्वारा संचालित हैं, जिसकी निगरानी जनजातीय कार्य विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा की जाती है।

आदिवासी विकासखण्डों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए जनजातीय कार्य विभाग उत्तरदायी है। शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और आयुक्त, आदिवासी विकास, विभाग के प्रमुख हैं। एमपी ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इन्सटीट्यूट्स सोसायटी, जो मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत है, ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन के लिए वर्ष 2001 में आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा अधिकृत की गई थी। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (ए.सी.टी.डी.)/जिला संयोजक आदिवासी कल्याण (डी.ओ.टी.डब्ल्यू) जिला स्तर पर एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के मुखिया क्रमशः प्राचार्य और अधीक्षक हैं तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) उनके निरीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

### 2.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

एस.टी. के लिये आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा अवधि 2012-13 से 2016-17 तक के लिए की गयी। लेखापरीक्षा उद्देश्य थे: (i) क्या पात्र हितग्राहियों को समाविष्ट करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा था?; (ii) क्या मानव संसाधन पर्याप्त थे?; (iii) क्या एक प्रभावी निगरानी तंत्र था?; (iv) एस.टी. आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि प्रबंधन कैसा था?

18 अप्रैल 2017 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी। शीर्ष स्तर पर आयुक्त, आदिवासी विकास और एमपी ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इन्सटीट्यूट्स सोसायटी के कार्यालयों में अभिलेखों की जांच की गयी। चार जिलों (धार, खरगौन, मंडला तथा शहडोल) जिनमें 32 आदिवासी विकासखण्ड हैं, मैदानी स्तर पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए थे। चार ए.सी.टी.डी. और चयनित नौ आदिवासी विकासखण्डों में नौ बी.ई.ओ. के कार्यालयों, 31 आवासीय विद्यालयों और 28 छात्रावासों के अभिलेखों की जांच की गयी जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.1** में वर्णित है। नमूना जांच किए गये आवासीय विद्यालय और छात्रावास, चयनित जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत हैं।

अगस्त 2017 में प्रारूप प्रतिवेदन जनजातीय कार्य विभाग को जारी किया गया था। 11 दिसम्बर 2017 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन के दौरान जनजातीय कार्य विभाग के उत्तर तथा व्यक्त विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। उत्तरों को शामिल करते हुए, एक संशोधित प्रारूप प्रतिवेदन अप्रैल 2018 में जनजातीय कार्य विभाग को जारी किया गया। हालांकि, संशोधित प्रतिवेदन के उत्तर अगस्त 2018 तक प्रतीक्षित थे।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी कंडिकाओं में दो खण्डों के अधीन चर्चा की गई है: खण्ड अ – केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत संचालित ई.एम.आर.एस.; एवं खण्ड ब – मुख्यतः राज्य योजनाओं के तहत संचालित अन्य आवासीय विद्यालय और छात्रावास।

चूंकि यह चयनित आवासीय विद्यालयों / छात्रावासों में एक लेखा परीक्षा जांच थी और अधिकांश लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकृति के हैं जो अन्य आवासीय विद्यालयों/ छात्रावासों, जो लेखापरीक्षा जांच में शामिल नहीं किये गये हैं, में परिलक्षित हो सकते हैं, इसलिए विभाग शेष आवासीय विद्यालयों/ छात्रावासों में स्थिति की आंतरिक जांच यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कि वे आवश्यकता और नियमों के अनुसार संचालित हैं, कर सकता है।

### खण्ड (अ) – एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.)

भारत सरकार ने राज्य के दूरदराज इलाकों में एस.टी. श्रेणी के छात्रों को माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा छह से 12) तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने के उद्देश्य से ई.एम.आर.एस. योजना आरम्भ (1997-98) की। योजना के तहत, भारत सरकार विद्यालय भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत लागत और विद्यालय संचालन के लिए निर्धारित दर से आवर्ती लागत प्रदाय करती है। राज्य शासन को विद्यालय, खेल के मैदान, छात्रावास, आवास-गृह आदि के लिए पर्याप्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराना है। राज्य शासन ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन और प्रभावी संचालन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है।

राज्य में 29 ई.एम.आर.एस. संचालित हैं, जो पांच चरणों<sup>4</sup> में खोले गए थे। राज्य स्तर पर ई.एम.आर.एस. के संचालन के लिए एमपी ट्रायबल वेलफेयर रसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इन्सटीट्यूट्स सोसायटी (सोसायटी) उत्तरदायी है। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री पदेन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग पदेन उपाध्यक्ष तथा आयुक्त, आदिवासी विकास सोसायटी के निदेशक मंडल के पदेन सचिव हैं। जिला स्तर पर ई.एम.आर.एस. के संचालन तथा नियंत्रण के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों के अधीन जिला निगरानी समितियां स्थापित की गई हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा में 29 ई.एम.आर.एस. में से छः<sup>5</sup> को आवृत किया गया।

### 2.1.3 ई.एम.आर.एस. का वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं (टी.ए.डी.पी.) विभाग, मध्य प्रदेश शासन को ई.एम.आर.एस. के तहत सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) प्रदाय करता है, जो इस बजट को आयुक्त, आदिवासी विकास को पुनरावृत्ति करती है, जो सोसायटी को निधियां जारी करता है। सोसायटी ई.एम.आर.एस. के संचालन के लिए कलेक्टर को और निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) को निधियां जारी करती है।

योजना के तहत, छात्रावास भवनों और कर्मचारी आवास-गृहों सहित विद्यालय भवन के लिए ₹ 12 करोड़ की पूंजीगत लागत अनावर्ती जी.आई.ए. के रूप में प्रदाय की जाती है। योजना के तहत विद्यालय के पहले वर्ष के लिए ₹ 42,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष की आवर्ती जी.आई.ए. प्रदान की जाती है, जिसे प्रति दूसरे वर्ष मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति, आदि के लिए 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक अनावर्ती वस्तुओं की खरीद जैसे रसोईघर, भोजन, छात्रावास, मनोरंजन, बगीचे आदि को शामिल करते हुए फर्नीचर/उपकरण, के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार प्रति विद्यालय ₹ 10 लाख की राशि की अनुमति है।

<sup>4</sup> प्रथम चरण (1999-2000) में आठ विद्यालय, दूसरे चरण (2005-06) में चार विद्यालय, तीसरे चरण (2010-11) में आठ विद्यालय, चौथे चरण (2014-15) में पांच विद्यालय तथा 5वें चरण (2015-16) में चार विद्यालय।

<sup>5</sup> धार (कुक्षी और धार), खरगौन, मंडला (सिझौरा और मंडला) और शहडोल

2012-13 से 2016-17 के दौरान, भारत सरकार से टी.ए.डी.पी. को ₹ 282.19 करोड़ का जी.आई.ए. प्राप्त हुआ, जो आयुक्त, आदिवासी विकास को स्थानांतरित किया गया, जिसने फिर सम्पूर्ण जी.आई.ए. सोसायटी को जारी किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयुक्त, आदिवासी विकास ने सोसायटी को निधि हस्तांतरण में यथोचित परिश्रम (due diligence) नहीं किया। सोसायटी के पदेन सचिव होने के कारण आयुक्त, आदिवासी विकास, सोसायटी के पास पड़ी अप्रयुक्त शेष राशियों से अवगत थे। हालांकि, अप्रयुक्त शेष राशियों को समायोजित किये बिना निधियां जारी की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 को सोसायटी के बैंक खातों में ₹ 113.84 करोड़ की बड़ी राशि जमा थी।

आगे, 2015-16 और 2016-17 की अवधि हेतु सोसायटी के खातों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण, सोसायटी द्वारा किये गये व्यय को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका। हालांकि, सोसायटी ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान उसके द्वारा किये गये व्यय के निम्नलिखित विवरण (तालिका 2.1.1) प्रदान किये।

तालिका 2.1.1: सोसायटी द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्व शेष	आवर्ती अनुदान	अनावर्ती अनुदान	बैंक से प्राप्त ब्याज	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंत शेष
2012-13	48.61	25.08	21.83	1.84	97.36	20.58	76.78
2013-14	76.78	25.63	0.00	2.66	105.07	35.35	69.72
2014-15	69.72	28.32	39.37	2.46	139.87	31.68	108.19
2015-16	108.19	30.09	50.00	1.43	189.71	30.15	159.56
2016-17	159.56	34.21	27.66	2.80	224.23	126.90	97.33
योग		143.33	138.86	11.19		244.66	

(स्रोत: टी.ए.डी.पी., आयुक्त, आदिवासी विकास और सोसायटी के अभिलेख)

2012-13 से 2016-17 के दौरान ₹ 97.33 करोड़ की बचत ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण में धीमी प्रगति, जैसा कि कंडिका 2.1.4.2 में वर्णित है, और प्रति वर्ष ₹ सात करोड़ से ₹ 13 करोड़ तक की सीमा में ई.एम.आर.एस. को निधि का हस्तांतरण, छात्रों के नामांकन के अनुपात में नहीं किए जाने के कारण थी। नामांकित छात्रों के अनुपात में ई.एम.आर.एस. को निधि हस्तांतरित न किए जाने का कारण न तो सोसायटी के अभिलेखों में उपलब्ध था और न ही अनुस्मारक पत्रों के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रदाय किया गया।

### निर्धारित लेखा-बहियों का संधारण न किया जाना

सोसायटी के उपनियमों के अनुसार, रोकड़ बही और अन्य संबंधित लेखों को सहायक सचिव (लेखा) द्वारा संधारित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि रोकड़ बही उचित रूप से संधारित नहीं की गई थी और आवश्यक जानकारी जैसे प्राप्त जी.आई.ए., प्रारंभिक तथा अंतशेष आदि सम्मिलित नहीं किए गए थे। सोसायटी ने अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे कि लेजर, बैंक समाधान पत्रक भी तैयार नहीं किए। बैंक विवरणों की जांच में पता चला कि 31 मार्च 2017 की स्थिति में, सोसायटी के ई.एम.आर.एस. बैंक खातों में ₹ 113.84 करोड़ के विरुद्ध सोसायटी के अभिलेखों ने अंतिम शेष ₹ 97.33 करोड़ सूचित किया। सोसायटी के वार्षिक लेखे जो वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के 90 दिनों के भीतर तैयार किये जाने थे, वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए तैयार नहीं किए गये थे क्योंकि सोसायटी सनदी लेखाकार (सी.ए.) को नियुक्त करने में विफल रही थी। सोसायटी के पदेन सचिव के रूप में आयुक्त, आदिवासी विकास

सोसायटी के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन खातों को अंतिम रूप देने में विफल रहे।

आवश्यक अभिलेखों की अनुपस्थिति संभावित दुरुपयोग और धोखाधड़ी के लिए एक खतरे का सूचक है, जैसा कि तथ्य भी है कि सोसायटी एक सी.ए. को नियुक्त करने में विफल रही और लेखे बकाया हैं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के अनिवार्य बही-खातों को संधारित करने और खातों को अंतिम रूप देने में विफलता की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विफलता जानबूझकर नहीं थी तथा दुरुपयोग और धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं थी, सतर्कता दृष्टिकोण से करनी चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को इस विफलता के लिए सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए तथा अविलंब उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए।

### अवास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण

2012-13 से 2016-17 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 282.19 करोड़ के जी.आई.ए. के लिए सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) की जांच और सोसायटी के ई.एम.आर.एस. बैंक खातों के साथ परस्पर सत्यापन से पता चला कि यू.सी. अवास्तविक थे, क्योंकि मार्च 2017 तक सोसायटी के ई.एम.आर.एस. बैंक खातों में ₹ 113.84 करोड़ (ब्याज सहित) की अप्रयुक्त शेष राशि थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सोसायटी के सचिव के रूप में आयुक्त, आदिवासी विकास ने यू.सी. के प्रस्तुतीकरण को अनुमोदित किया था। इस प्रकार, आयुक्त, आदिवासी विकास, ₹ 113.84 के अवास्तविक यू.सी. प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

### अनुशंसा

भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए तथा उचित विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए।

### ई.एम.आर.एस. के निर्माण के लिए असमायोजित/न पता लगाए जाने योग्य अग्रिम

सोसायटी ने 2001-02 से 2008-09 के दौरान ई.एम.आर.एस. के भवन निर्माण के लिए 18 जिला कलेक्टरों<sup>6</sup> को ₹ 30.69 करोड़ का अग्रिम जारी किया। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित पता चला:

✓ आठ से 15 वर्ष पहले स्वीकृत ₹ 30.69 करोड़ के अग्रिम आज दिनांक (अगस्त 2018) तक असमायोजित थे। सोसायटी द्वारा असमायोजित अग्रिमों के

<sup>6</sup> अनूपपुर (₹ 1.66 करोड़), बड़वानी (₹ 1.61 करोड़), बालाघाट (₹ 2.00 करोड़), बैतूल (₹ 1.62 करोड़), छिंदवाड़ा (₹ 1.00 करोड़), धार (₹ 4.02 करोड़), डिण्डोरी (₹ 0.50 करोड़), झाबुआ (₹ 2.10 करोड़), खण्डवा (₹ 2.00 करोड़), खरगौन (₹ 2.00 करोड़), मण्डला (₹ 2.01 करोड़), रतलाम (₹ 2.21 करोड़), सिवनी (₹ 2.37 करोड़), शहडोल (₹ 2.00 करोड़), शिवपुरी (₹ 1.00 करोड़), सीधी (₹ 1.00 करोड़), श्योपुर (₹ 0.99 करोड़) तथा उमरिया (₹ 0.60 करोड़)।

समायोजन/वसूली के लिए की गई कार्रवाई का कोई प्रमाण लेखापरीक्षा को नहीं मिला।

✓ ₹ 1.00 करोड़ और ₹ 0.99 करोड़ के अग्रिम क्रमशः शिवपुरी (2006–07) और श्योपुर (2008–09) के कलेक्टरों को जारी किये गये थे, जबकि इन जिलों में ई.एम.आर.एस. की कोई योजना नहीं थी या स्थापित नहीं थी।

✓ इसी तरह, 2006–07 से 2008–09 के दौरान बालाघाट, खंडवा, खरगौन और शहडोल जिलों में से प्रत्येक को ₹ 2.00 करोड़ ( योग: ₹ 8.00 करोड़) के अग्रिम जारी किए गए, जबकि 2009–10 तक इन जिलों में कोई ई.एम.आर.एस. स्वीकृत नहीं था। बाद में, ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण के लिए इन जिलों में से प्रत्येक को ₹ 12.00 करोड़ (योग: ₹ 48.00 करोड़) जारी किए गए। हालांकि, पूर्व के ₹ 8.00 करोड़ के अग्रिम असमायोजित बने रहे।

✓ नमूना जांच किये गये चार जिलों में, ₹ 8.00 करोड़<sup>8</sup> में से ₹ 6.03 करोड़<sup>9</sup> के अग्रिम के अभिलेख तीन जिला कलेक्टरों (धार, मंडला और शहडोल) के अभिलेखों में नहीं पाये गये, और दो जिलों (धार और खरगौन) में ₹ 4.00 करोड़ के अग्रिम यद्यपि पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उपयोग कर लिए गये थे, सोसायटी की बहियों में असमायोजित थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का वादा किया।

## अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को सतर्कता दृष्टिकोण से लंबी अवधि से पड़े असमायोजित अग्रिम के प्रकरणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दुरुपयोग या धोखाधड़ी नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग और मध्य प्रदेश शासन को अप्रयुक्त अग्रिमों को वापस/समायोजित करने में विफल होने के लिए जिला और सोसायटी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए। आयुक्त, आदिवासी विकास, जो सोसायटी के पदेन सचिव भी हैं, को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले समायोजन के लिए बकाया अग्रिमों की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

### 2.1.4 कार्यक्रम क्रियान्वयन

#### 2.1.4.1 ई.एम.आर.एस. में शिक्षा की गुणवत्ता

ई.एम.आर.एस. के दिशा निर्देश (जून 2010) निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह से ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन और प्रभावी संचालन के लिये जिम्मेदार है, और उसे शैक्षणिक एवं पाठ्येत्तर उत्कृष्टता के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के चयन में उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन ने ई.एम.आर.एस. में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2013 अनुमोदित (जून 2013) किए। हालांकि, ई.एम.आर.एस. में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी (परिशिष्ट 2.1.2)। 29 ई.एम.आर.एस. में से 15 ई.एम.आर.एस. में प्राचार्यों के पद रिक्त पड़े थे। इसी तरह, व्याख्याताओं के 120 पदों के विरुद्ध, 95 पद रिक्त थे और शिक्षकों के 180 पदों में से, 152 रिक्त थे।

<sup>7</sup> 2010–11 में बालाघाट, खण्डवा तथा शहडोल और 2015–16 में खरगौन को।

<sup>8</sup> धार: ₹ 4.02 करोड़ (2001–09 के दौरान जारी), मण्डला: ₹ 2.01 करोड़ (2001–05 के दौरान जारी) तथा शहडोल: ₹ 2.00 करोड़ (2006–09 के दौरान जारी)।

<sup>9</sup> धार: ₹ 2.02 करोड़, मण्डला: ₹ 2.01 करोड़, शहडोल: ₹ 2.00 करोड़।

व्याख्याताओं और शिक्षकों का कोई भी पद नियमित कर्मचारियों द्वारा नहीं भरा गया था। शिल्प शिक्षकों, तबला शिक्षकों, सहायक विज्ञान शिक्षकों, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और सहायक शिक्षकों के पद किसी भी ई.एम.आर.एस. में नहीं भरे गए थे। मध्यप्रदेश के ई.एम.आर.एस. में योग्य और स्थायी शिक्षकों को प्रदान करने में राज्य सरकार की विफलता पर भारत सरकार की चिंता को तत्कालीन राज्य मंत्री, जनजातीय मामले, भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री म.प्र.शा. को भी सूचित (मई 2016) किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिये आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा उठाये गए उपाय केवल आंतरायिक थे। आयुक्त, आदिवासी विकास ने शिक्षकों की भर्ती के लिए व्यापम<sup>10</sup> से अनुरोध (जून 2014, जुलाई 2014 और जून 2015) किया था। हालांकि, व्यापम द्वारा शिक्षकों की भर्ती न किए जाने के कारण; अभिलेख से स्पष्ट नहीं थे। सोसायटी के संचालक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त (अप्रैल 2015) के अनुसार, व्यापम अन्य प्रक्रियाओं<sup>11</sup> में शामिल होने के कारण शिक्षकों की भर्ती करने में सक्षम नहीं था। जनजातीय कार्य विभाग ने नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में प्रतीक्षा सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से प्राचार्यों/व्याख्याताओं/शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों को उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से भी अनुरोध (नवम्बर 2016 और जनवरी 2017) किया था।

परिणामस्वरूप, संविदा शिक्षकों या अतिथि शिक्षकों को रखते हुए रिक्तियों को केवल आंशिक रूप से भरा गया था। हालांकि, इस तदर्थ व्यवस्था ने ई.एम.आर.एस. में विषयवार शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसने ई.एम.आर.एस. में परिणामों की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया जैसा कि नीचे उल्लेखित है:-

ई.एम.आर.एस. के कक्षा 12 वीं के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत, ई.एम.आर.एस. के कक्षा 10 वीं के छात्रों के परिणाम और सी.बी.एस.ई.<sup>12</sup> के अजमेर क्षेत्र में कक्षा 12 वीं के छात्रों के परिणाम की तुलना में बहुत खराब था, जैसा कि तालिका 2.1.2 में वर्णित है।

तालिका 2.1.2: कक्षा 12 वीं की परीक्षा में ई.एम.आर.एस. का प्रदर्शन

वर्ष	ई.एम.आर.एस. में कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत	ई.एम.आर.एस. में कक्षा 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत	सी.बी.एस.ई. के अजमेर क्षेत्र में कक्षा 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत
2012-13	99.70	40.95	86.26
2013-14	100.00	53.69	86.22
2014-15	95.90	54.39	85.17
2015-16	93.65	78.00	86.64
2016-17	96.38	65.37	84.69

(स्रोत: सोसायटी द्वारा प्रदाय आंकड़े एवं सी.बी.एस.ई. की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी)

ई.एम.आर.एस. में परिणामों की स्थिति चिंता का विषय है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि ई.एम.आर.एस. में छात्रों के प्रवेश के लिए एक कठिन चयन प्रक्रिया है

<sup>10</sup> व्यापम मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम 2007 के तहत गठित राज्य शासन की भर्ती निकाय है। राज्य शासन ने सूचित किया (जनवरी 2015) कि व्यापम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत नहीं आता है।

<sup>11</sup> अभिव्यक्ति 'अन्य प्रक्रिया' कार्य विवरण में स्पष्ट नहीं किया गया है।

<sup>12</sup> राज्य में ई.एम.आर.एस. के छात्र, सी.बी.एस.ई. के अजमेर क्षेत्र में नामांकित हैं।



और इन विद्यालयों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अन्यथा अन्य शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, शिक्षकों की भर्ती में जनजातीय कार्य विभाग की विफलता के कारण राज्य में एस.टी. के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालयों के रूप में ई.एम.आर.एस. स्थापित करने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने स्वीकार किया कि विषयवार/अंग्रेजी माध्यम के अतिथि शिक्षकों की अनुपलब्धता और अतिथि शिक्षकों को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने आगे कहा कि विभागीय ऑनलाईन परीक्षा के माध्यम से प्राचार्यों/व्याख्याताओं/शिक्षकों की भर्ती के लिये प्रयास किये जा रहे थे।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को ई.एम.आर.एस. में प्राचार्यों/व्याख्याताओं/शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिये और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संविदा/अतिथि शिक्षकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

#### 2.1.4.2 ई.एम.आर.एस. भवनों का निर्माण

2010-11 से 2016-17 के बीच भारत सरकार ने 17 ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता (जी.आई.ए.) प्रति भवन ₹ 12.00 करोड़ स्वीकृत किया। दिसम्बर 2017 की स्थिति में इन ई.एम.आर.एस. के निर्माण की स्थिति तालिका 2.1.3 में दी गई है।

तालिका 2.1.3: दिसम्बर 2017 की स्थिति में ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
2010-11	8	7	1
2014-15	5	निरंक	5
2015-16	4	निरंक	4
<b>कुल</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

(स्रोत: सोसायटी के द्वारा प्रदाय आंकड़े)

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 अपूर्ण भवनों के लिए प्राप्त ₹ 120 करोड़ के जी.आई.ए. में से पी.डब्ल्यू.डी. (निर्माण एजेंसी) ने ₹ 87.64 करोड़ (इसे जारी किये गये ₹ 100.70 करोड़ में से)<sup>13</sup> व्यय किया था। इन ई.एम.आर.एस. के निर्माण की धीमी प्रगति का मुख्य कारण भूमि चयन में दो महीने से 17 महीने तक का विलम्ब था। हालांकि, टीएडी के विभागीय निर्माण नियमों के अनुसार, ई.एम.आर.एस. के भवनों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति से पहले, ए.सी.टी.डी. भूमि चयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। चूंकि ये ई.एम.आर.एस. अपूर्ण भवनों/अस्थायी व्यवस्थाओं में संचालित हो रहे थे, इसलिए छात्रों को उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए उल्लेखित सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने पी.डब्ल्यू.डी. को विफलता का जिम्मेदार ठहराया, जिसने निर्धारित 18 महीनों के भीतर काम पूरा नहीं किया। आगे, मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में इन कार्यों को जुलाई

<sup>13</sup> शेष राशि में से ₹ 13.06 करोड़ पी.डब्ल्यू.डी. के पास पड़ा था तथा ₹ 19.30 करोड़ सोसायटी के पास पड़ा था।

2018 तक (ई.एम.आर.एस. बुधनी जिला सिहोर, खरगौन, मण्डला, सेंधवा जिला बडवानी और चंद्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर के संबंध में) और जुलाई 2019 तक (ई.एम.आर.एस. गरडावद जिला धार, सिंगरौली, मैहर और चित्रकूट जिला सतना के संबंध में) पूरा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के उत्तर में भूमि चयन सुनिश्चित किए बिना प्रशासनिक स्वीकृति देने में जनजातीय कार्य विभाग की विफलता को संबोधित नहीं किया गया।

### 2.1.4.3 संचालक मंडल और जिला स्तरीय समिति की बैठकें

सोसायटी उप-नियम निर्धारित करते हैं कि संचालक मंडल को वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार, और यदि आवश्यक हो तो, एक बार से अधिक ऐसी तिथियों और ऐसे स्थानों पर जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जाए, मिलना चाहिए। लेखापरीक्षा ने, यद्यपि, देखा कि 2012-17 के दौरान संचालक मंडल निर्धारित 20 बैठकों के विरुद्ध केवल सात बार मिले थे।

जिला स्तरीय समितियों को भवनों की व्यवस्था और निर्माण की गुणवत्ता नियंत्रण, ई.एम.आर.एस. में बुनियादी सुविधायें, शिक्षा में नवाचार, प्राप्त निधि के उपयोग आदि को सुनिश्चित करना था। इन समितियों का प्रत्येक वर्ष चार बार मिलना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने, हालांकि, देखा कि नमूना जांच किये गये छह ई.एम.आर.एस. में, 2012-17 के दौरान जिला स्तरीय समिति की निर्धारित 76 बैठकों के विरुद्ध केवल 12 बैठकें हुई थीं जैसा कि परिशिष्ट 2.1.3 में वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

## खण्ड (ब) – एस.टी. के लिए अन्य आवासीय विद्यालय और छात्रावास

### 2.1.5 बजट प्रावधान और व्यय

वर्ष 2012-17 के दौरान, राज्य सरकार ने एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों पर ₹ 2,441.46 करोड़ का व्यय किया, जिसमें ₹ 71.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता (50 छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹ 43.50 करोड़ और 92 आश्रम शाला भवनों के निर्माण के लिए ₹ 27.81 करोड़) शामिल थी। 2012-13 से 2016-17 के दौरान एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों पर बजट प्रावधान और व्यय तालिका 2.1.4 में वर्णित है।

तालिका 2.1.4: एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों पर बजट प्रावधान एवं व्यय

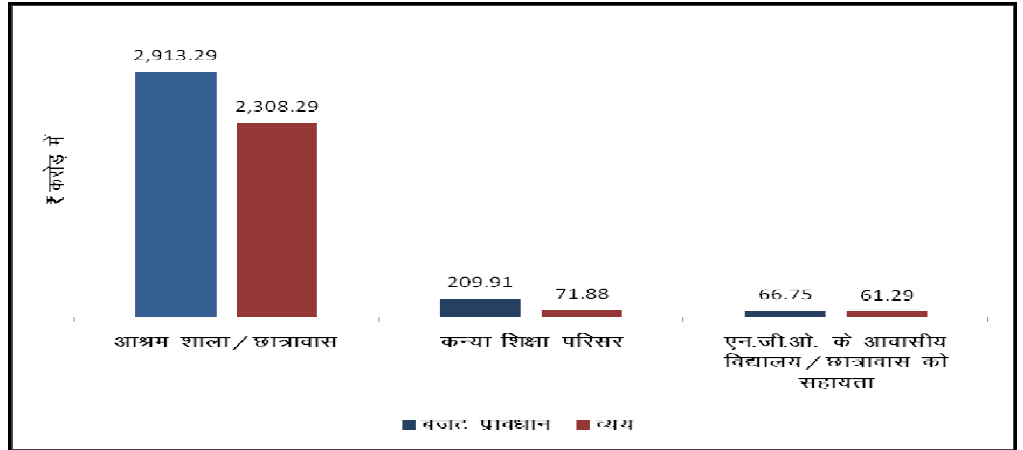
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन			व्यय	बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत
	बजट प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल आबंटन		
2012-13	431.28	(-) 25.22	406.06	404.11	27.17
2013-14	546.04	(-) 60.12	485.92	423.68	122.36
2014-15	632.43	(-) 116.60	515.83	464.48	167.95
2015-16	785.63	(-) 235.98	549.65	531.88	253.75
2016-17	794.57	(-) 142.89	651.68	617.31	177.26
योग	3,189.95	(-) 580.81	2,609.14	2,441.46	748.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोजन लेखे)

2012-17 के दौरान योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय चार्ट 2.1.1 में दिये गये हैं।

चार्ट 2.1.1: 2012-17 के दौरान योजनावार बजट प्रावधान और व्यय



(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत, मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति और स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियों की वजह से देय वेतन पर कम व्यय के कारण थी, जैसा उत्तरवर्ती पैराग्राफ 2.1.6.4 और 2.1.6.6 में चर्चा की गयी है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में वास्तविक बजट प्रावधान बनाए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अपने बजट वास्तविक बनाने की कोशिश करने के बजाय, जनजातीय कार्य विभाग को बजट निधियों को खर्च करने में असमर्थता के मूल कारण को संबोधित करना चाहिए।

## 2.1.6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

### 2.1.6.1 बिना योजना तैयार किए छात्रावासों का उन्नयन

जनजातीय कार्य विभाग ने 330 एस.टी. प्री-मैट्रिक छात्रावासों को 50 सीटर छात्रावासों में उन्नयित (दिसम्बर 2012) किया। हालांकि, इस उन्नयन के परिणामस्वरूप इन छात्रावासों की आवास क्षमता में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई। स्वयं के भवन में संचालित हो रहे 318 उन्नयित छात्रावासों में से केवल 71 उन्नयित छात्रावासों में नये भवन/अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया था। इस प्रकार, 247 (75 प्रतिशत) उन्नयित छात्रावासों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध पर्याप्त आवास नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि, एक चारपाई दो छात्रों द्वारा साझा किया जा रहा था, शौचालयों एवं स्नानागारों की कमी आदि।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि मई 2010 में मध्य प्रदेश विधान सभा के एक विशेष सत्र में पारित संकल्प को ध्यान में रखते हुये छात्रावासों का उन्नयन तत्काल किया गया था, जिसके कारण छात्रावासों के 50 सीटर आवास में उन्नयन से पहले नये भवनों/अतिरिक्त कक्षों का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सभी उन्नयित छात्रावासों में पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान करने हेतु भवन/अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की योजना शीघ्र ही बनायी जाएगी।

भविष्य में, मानदण्डों के अनुसार भवनों की उपलब्धता के बाद ही छात्रावासों का उन्नयन किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में पारित संकल्प में पर्याप्त बुनियादी ढांचे (आवास, शौचालय, स्नानागार इत्यादि) की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना छात्रावासों को उन्नयित करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित नहीं किया गया था। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग का उत्तर विशेष सत्र में संकल्प और दिसम्बर 2012 के विभागीय आदेश के बीच दो वर्ष से अधिक के अंतर के कारण को भी सम्बोधित नहीं करता, जो कि 247 उन्नयित छात्रावासों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु योजना बनाने के लिये जनजातीय कार्य विभाग के लिये पर्याप्त समय था। इस प्रकार, आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए बिना छात्रावासों के उन्नयन करने का जनजातीय कार्य विभाग का आदेश दोषपूर्ण था।

### अनुशंसा

*जनजातीय कार्य विभाग को 247 छात्रावासों, जो दिसम्बर 2012 में उन्नयित किए गये थे, में तत्काल आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।*

#### 2.1.6.2 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में छात्रों का चयन

छात्रावास नियम 1966-67 एवं आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 1998) के अनुसार, आश्रम शालाओं और छात्रावासों में छात्रों का चयन, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.), उनके निवास स्थान से आठ किलोमीटर (लड़कों के लिये)/ तीन किलोमीटर (लड़कियों के लिये) के क्षेत्र में किसी भी शैक्षणिक संस्थान की अनुपलब्धता, निवास स्थान से आश्रम/छात्रावास की दूरी और उनकी अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक चयन समिति द्वारा किया जाना था।

नमूना जांच किए गये जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) ने आश्रम शालाओं और छात्रावासों में प्रवेश के लिए विकास खण्ड के विद्यालयों में अधिसूचनाएं अग्रेषित की थीं और जांच एवं छात्रों के चयन के लिए बी.ई.ओ. द्वारा एक चयन समिति गठित की गई थी। हालांकि, चयन समिति ने आश्रम शाला/छात्रावास से निवास स्थान की दूरी, प्रवीणता सूची, और बी.पी.एल. आदि चयन मानकों के पालन किए बिना, मनमाने ढंग से छात्रों का चयन किया। ए.सी.टी.डी., जो छात्रों के चयन के परिवीक्षण के लिये उत्तरदायी थे, वे भी चयन मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया कि भविष्य में नियमों के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर 2017 में निर्देश जारी किए गये थे।

#### 2.1.6.3 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में एस.टी. छात्रों के अलावा अन्य का प्रवेश

छात्रावास नियम 1966-67 और जनजातीय कार्य विभाग के आदेश (जुलाई 1973) में आश्रम शालाओं और छात्रावासों में 90 प्रतिशत छात्र एस.टी. श्रेणी से, पांच प्रतिशत अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से और पांच प्रतिशत अन्य श्रेणी से, के प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, आदिवासी विकास के आदेश (अप्रैल 1998) में दिव्यांग छात्रों के लिए तीन प्रतिशत स्थान के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ए.सी.टी.डी. उत्तरदायी थे।

चयनित 49 आश्रम शालाओं/छात्रावासों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रवेश के लिए श्रेणीवार कोटा का पालन नहीं किया गया जैसा कि तालिका 2.1.5 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.1.5: स्वीकृत सीटों के विरुद्ध श्रेणीवार छात्रों का विवरण

वर्ष	स्वीकृत सीट	चयनित छात्र				दिव्यांग छात्र
		एस.टी.	एस.सी.	अन्य	योग	
2012-13	3,752	3,451	41	8	3,500	19
2013-14	3,786	3,562	32	6	3,600	15
2014-15	3,820	3,589	29	24	3,642	11
2015-16	3,820	3,715	16	39	3,770	13
2016-17	3,820	3,767	11	27	3,805	11
योग	18,998	18,084 (98.72 प्रतिशत)	129 (0.71 प्रतिशत)	104 (0.57 प्रतिशत)	18,317	69 (0.36 प्रतिशत)

(स्रोत: चयनित आश्रम शालायें/ छात्रावास)

ए.सी.टी.डी. ने अन्य श्रेणी के छात्रों के कोटा के पालन न होने के लिए, इन क्षेत्रों में उच्च जनजातीय आबादी, जिसके कारण सभी सीटें एस.टी. छात्रों से भरी हुई हैं, को जिम्मेदार बताया।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि आरक्षण प्रावधानों के कड़ाई से पालन के लिए सभी जिला कलेक्टरों/ ए.सी.टी.डी. को निर्देश जारी किये जाएंगे।

#### 2.1.6.4 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों का निर्माण

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयुक्त, आदिवासी विकास ने 2012-17 के दौरान 355 आश्रम शालाओं/ छात्रावासों/ कन्या शिक्षा परिसरों (के.एस.पी.) के लिए भवनों का निर्माण स्वीकृत किया था। निर्माण की स्थिति तालिका 2.1.6 में दी गई है।

तालिका 2.1.6: आश्रम शालाओं/ छात्रावासों/ के.एस.पी. के निर्माण की स्थिति

स्वीकृति वर्ष	कुल स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
2012-13	84	79	3	2
2013-14	53	51	2	0
2014-15	52	39	10	3
2015-16	52	17	27	8
2016-17	114	1	35	78
योग	355	187	77	91

(स्रोत: आयुक्त, आदिवासी विकास का अभिलेख)

अपूर्ण/अप्रारंभ निर्माण कार्यों में 64 छात्रावास, 39 आश्रम शालायें और 65 के.एस.पी. शामिल थे। पी.डब्ल्यू.डी. और आयुक्त, आदिवासी विकास के अभिलेखों की जांच में पता चला कि इन भवनों के निर्माण में धीमी प्रगति मुख्य रूप से स्थल चयन में देरी, भूमि की अनुपलब्धता और भूमि विवाद के कारण हुई थी। हालांकि, जनजातीय कार्य विभाग के विभागीय निर्माण नियमों के अनुसार, आश्रम शालाओं/छात्रावासों/के.एस.पी. के लिए स्थल चयन, प्रशासकीय स्वीकृति से पहले किया जाना था जिसके लिए ए.सी.टी.डी. उत्तरदायी थे। स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

अभिलेखों की आगे जांच में पता चला कि निर्माण एजेन्सियों<sup>14</sup> को ₹ 11.44 करोड़ हस्तांतरण के बाद भी 2012-13 से पहले स्वीकृत 17 आश्रम शालाओं/छात्रावासों का निर्माण मार्च 2017 की स्थिति में अपूर्ण था, जिनमें से ₹ 4.33 करोड़ निर्माण एजेन्सियों के पास अव्ययित शेष थे। इन 17 अपूर्ण आश्रम शालाओं/छात्रावासों में से, तीन आश्रम शालायें<sup>15</sup> चयनित जिला (मंडला) में स्थित थीं। इन तीन आश्रम शाला भवनों में से प्रत्येक के लिए ₹ 14.14 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां मार्च 2000 (एस.टी. बालिका आश्रम शाला, घुघरी और एस.टी. बालक आश्रम शाला, कापा) और मार्च 2003 (एस.टी. बालिका आश्रम शाला, खजरी) में जारी की गई थीं। वर्ष 2001-07 के दौरान, ए.सी.टी.डी., मण्डला ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) मंडला, जो सभी तीनों भवनों के लिए निर्माण एजेन्सी थी, को ₹ 58.33 लाख जारी किए। कार्यपालन यंत्री, आर.ई.एस., मण्डला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (मई 2017) में पता चला कि आर.ई.एस. ने इन कार्यों पर ₹ 47.10 लाख खर्च किए थे लेकिन आयुक्त, आदिवासी विकास से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन न होने के कारण निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था। उचित स्थल चयन में देरी एवं मजदूरी और सामग्री की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप कार्यों की लागत में हुई वृद्धि के कारण आर.ई.एस. द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की मांग (नवंबर 2010) की गई। लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल-मई 2017) के दौरान देखा कि निर्माण स्थलों को आर.ई.एस. द्वारा परित्यक्त किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दिखाया गया है।

<b>मण्डला जिले में तीन आश्रम शालाओं के परित्यक्त कार्य</b>	
	
<b>एस.टी. बालिका आश्रम शाला घुघरी, मण्डला का अपूर्ण निर्माण</b>	<b>एस.टी. बालक आश्रम शाला कापा, मण्डला का अपूर्ण निर्माण</b>
	
<b>एस.टी. बालिका आश्रम शाला खजरी, मण्डला का अपूर्ण निर्माण</b>	<b>एस.टी. बालिका आश्रम शाला खजरी, मण्डला की छात्राएं कक्षाओं के अभाव में बरामदे में पढ़ती हुईं।</b>

<sup>14</sup> आठ भवनों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. और नौ भवनों के लिये आर.ई.एस.।

<sup>15</sup> एस.टी. बालिका आश्रम शाला, घुघरी, एस.टी. बालक आश्रम शाला, कापा और एस.टी. आश्रम शाला, खजरी।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के लिए आर.ई.एस. के प्रस्ताव को, पूर्व संस्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अनुशंसा के साथ निरस्त (सितम्बर 2017) कर दिया गया था और सम्बन्धित विभाग से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया जा रहा था। उच्च स्तर पर आवश्यक समीक्षा/जाँच के बाद कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगस्त 2018 तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप तीन आश्रम शालाओं के परित्यक्त निर्माण कार्यों पर ₹ 47.10 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

### 2.1.6.5 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में अपूर्ण आधारभूत संरचना/सुविधाएं

नमूना जांच किए गये 53 (25 लड़कों और 28 लड़कियों) आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

- योजनाओं के अनुमोदित अभिन्यास (lay out plans) के अनुसार, 50-सीटर छात्रावास में छः शौचालयों की आवश्यकता थी। हालांकि, 36 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में मानदण्डों के विरुद्ध एक और 15 शौचालयों के बीच की सीमा में कमी थी।
- 24 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में भोजन कक्ष का निर्माण नहीं किया गया था और छात्र बरामदे/कक्षा में भोजन कर रहे थे। 22 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के छात्रों को भोजन करने के लिए फर्श पर बैठना पड़ा क्योंकि भोजन की मेजें नहीं क्रय की गई थीं।
- 13 आवासीय विद्यालयों और नौ छात्रावासों में अधीक्षकों के लिए आवास का निर्माण नहीं किया गया था, जिसके कारण सात आवासीय विद्यालयों और नौ छात्रावासों में अधीक्षक नहीं रह रहे थे। शेष छह आवासीय विद्यालयों के अधीक्षक छात्रावास में छात्रों के साथ ही रह रहे थे।
- नौ बालक और चार बालिकाओं के आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में कोई चाहरदीवारी नहीं थी। 52 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप नहीं था, हालांकि 2012-17 के दौरान इन आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 13 में 69 दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे थे।
- स्थान की कमी के कारण 41 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में 3,674 छात्रों के विरुद्ध केवल 2,094 चारपाई (57 प्रतिशत) उपलब्ध थे। इन आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में चारपाईयों की कमी की सीमा चार से 130 थी। जिसके फलस्वरूप, दो छात्रों द्वारा एक चारपाई साझा किया जा रहा था। आगे, 37 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की खिड़कियां मच्छर जाली से नहीं ढकी थीं।
- 31 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में खेल सामग्री उपलब्ध नहीं थी और 43 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में पुस्तकालय नहीं था।
- 11 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रात्रिकालीन चौकीदार तैनात नहीं किया गया था, जिनमें से चार बालिका आवासीय विद्यालय/छात्रावास थे।
- सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 18 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता था।

जनजातीय कार्य विभाग के आदेशों (जून 2013 और जून 2014) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं जैसे अध्ययन सामग्री, फर्नीचर, खेल सामग्री, सुरक्षित पानी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में क्रय नियमों के अनुसार सामग्रियों की खरीद के उद्देश्य से पालक समितियाँ<sup>16</sup> बनाई जानी है। अधीक्षक और बी.ई.ओ. से प्रत्येक आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पालक समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित करनी अपेक्षित थी। हालांकि, 2013-17 के दौरान नमूना जांच किए गये 51 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में 804 बैठकों के विरुद्ध 365 बैठकों की कमी थी। आगे, पालक समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की जांच से पता चला कि चयनित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियों पर इनकी बैठकों में चर्चा नहीं की गई थी। एन.जी.ओ. द्वारा संचालित दो आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में कोई पालक समिति नहीं बनाई गई थी।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

### अनुशंसा

*जनजातीय कार्य विभाग को प्रत्येक आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पालक समिति का गठन और वे प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं हों।*

#### 2.1.6.6 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में मानव संसाधन की तैनाती

##### • कन्या आश्रम शालाओं/छात्रावासों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती

आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2011) के अनुसार, कन्या आश्रम शालाओं/छात्रावासों में सभी कर्मचारियों को महिला होना चाहिए। अधीक्षक और कर्मचारियों से आश्रम शालाओं/छात्रावासों के परिसर में, जहां निवास सुविधा उपलब्ध है, रहना अपेक्षित है।

नमूना जांच किये गये चार जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 116 कन्या आश्रम शालाओं/छात्रावासों में 199 पुरुष कर्मचारी तैनात किए गये थे। इस प्रकार, आयुक्त, आदिवासी विकास के आदेशों का पालन करने में ए.सी.टी.डी. असफल रहे। लेखापरीक्षा ने देखा कि जनजातीय कार्य विभाग के पास आश्रम शालाओं/छात्रावासों में कर्मचारियों की तैनाती के परीक्षण और जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और प्राथमिकता पर सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

##### • आश्रम शालाओं/छात्रावासों में अधीक्षकों की तैनाती

आयुक्त, आदिवासी विकास के परिपत्रों (मई 1982 और मई 1999) के अनुसार, एस.टी. आश्रम शालाओं/छात्रावासों में एस.टी. श्रेणी के अधीक्षक ही तैनात किए जाने हैं। आगे, सभी कलेक्टरों को निर्देशित (मई 1996) किया गया था कि एस.टी. श्रेणी में अधीक्षकों

<sup>16</sup> छात्रों के माता-पिता, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रहने वाले प्रत्येक कक्षा के दो छात्र, जिन्होंने उच्चतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त किया हो और सम्बन्धित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के प्रमुख पालक समिति के सदस्य हैं।



की अनुपलब्धता की स्थिति में, अन्य जिलों/संभागों के अधीक्षकों को पदस्थ करने का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

नमूना जांच किये गये चार जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 578 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में से 107 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में अधीक्षक एस.टी. के अलावा अन्य श्रेणी से थे। हालांकि, संबंधित कलेक्टरों ने अन्य जिलों/संभागों से एस.टी. श्रेणी के अधीक्षकों को पदस्थ करने के लिए आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्ताव नहीं भेजे थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

#### • के.एस.पी. में शिक्षकों की कमी

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत एक विद्यालय हेतु मानदंडों और मानकों के अनुसार, उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए ताकि प्रत्येक (1) विज्ञान और गणित, (2) सामाजिक अध्ययन, और (3) भाषा के लिये कम से कम एक शिक्षक हो। ये मानदंड स्पष्ट रूप से एकल शिक्षक स्कूलों को प्रतिबंधित करते हैं।

तथापि लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, 16 के.एस.पी. में से 10 के.एस.पी. में केवल एक प्राचार्य था, कोई शिक्षक नहीं था; एक के.एस.पी. में केवल एक प्राचार्य और एक शिक्षक था; पांच के.एस.पी. में केवल एक प्राचार्य और दो शिक्षक थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि के.एस.पी. के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

#### 2.1.6.7 आश्रम शालाओं/छात्रावासों का निरीक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने आश्रम शालाओं/छात्रावासों के सुचारु कार्य हेतु नियमित निरीक्षण के लिए रोस्टर निर्धारित (मई 2006) किया था। आगे, प्रत्येक आश्रम शाला/छात्रावास का त्रैमासिक निरीक्षण ए.सी.टी.डी. द्वारा और मासिक निरीक्षण बी.ई.ओ. द्वारा निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किये गये जिलों में देखा कि कलेक्टरों ने आश्रम शालाओं और छात्रावासों के निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार नहीं किए थे। 2012-17 के दौरान नमूना जांच किए गये ए.सी.टी.डी. में आश्रम शालाओं और छात्रावासों के निरीक्षण में कमी 72 प्रतिशत और 81 प्रतिशत की सीमा के बीच थी और नमूना जांच किए गये बी.ई.ओ. में, कमी 54 प्रतिशत और 58 प्रतिशत की सीमा के बीच थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि आयुक्त, आदिवासी विकास निरीक्षणों के पर्यवेक्षण में असफल रहे, और जिलों ने भी मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं भेजा।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

### 2.1.7 अन्य अनियमितताएं

#### 2.1.7.1 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के लिए सामग्री का क्रय

मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम सामग्री क्रय के लिए निम्नलिखित विधियों को निर्धारित करते हैं:

संहितागत प्रावधान	सामग्री का मूल्य	क्रय का तरीका
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 1974 के अनुसार	₹ 1,000 तक	बिना निविदा बुलाये
	₹ 1,000 से अधिक किन्तु ₹ 25,000 से अधिक नहीं	सीमित निविदा द्वारा
	₹ 25,000 से अधिक	खुली निविदा द्वारा
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार	₹ 20,000 तक	बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के
	₹ 20,000 से अधिक और ₹ एक लाख तक	क्रय समिति द्वारा
	₹ एक से ₹ पांच लाख के बीच	सीमित निविदा द्वारा
	₹ 5.00 लाख से अधिक	खुली निविदा द्वारा

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 34 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों ने कोटेशन, निविदा आमंत्रण और क्रय समिति के अनुमोदन के बिना ₹ 1.40 करोड़ की लागत की सामग्री क्रय की। आगे, 34 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 26 ने उच्च अधिकारियों की स्वीकृति/अनुमति से बचने के लिए निविदाओं को विभाजित करने का सहारा लिया जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.4** में वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, और जिन्होंने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया है उपयुक्त सुधारात्मक उपाय के साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

### 2.1.8 रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण

आयुक्त, आदिवासी विकास के निर्देश (जनवरी 2009 और जून 2011) आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के छात्रों की मासिक स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित करते हैं। आयुक्त, आदिवासी विकास ने इस उद्देश्य के लिये, कलेक्टरों को, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) के साथ परामर्श कर, डाक्टरों के दल गठित करने का निर्देश (मई 2016) दिया था।

तथापि 2012-17 के दौरान नमूना जांच किए गये 59 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के अभिलेखों की जांच में मासिक स्वास्थ्य परीक्षणों में 86.53 प्रतिशत की कमी का पता चला।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

#### **सिकल सेल एनीमिया<sup>17</sup> की जांच के लिए शिविर**

आयुक्त, आदिवासी विकास ने जनजातीय विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों और छात्रावासों में सिकल सेल एनीमिया (एस.सी.ए.) के अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण और जांच के प्रबंधन के निर्देश (नवम्बर 2014) दिये थे। स्वास्थ्य कार्ड एस.सी.ए. की स्थिति दर्शाते हुए प्रत्येक बच्चे को जारी किए जाने थे। ए.सी.टी.डी. और जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रत्येक आदिवासी विकासखण्ड में एस.सी.ए. के परीक्षण के लिए शिविर आयोजित करने के लिए उत्तरदायी थे। इस उद्देश्य के लिए, आयुक्त, आदिवासी विकास ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 17 जिला कलेक्टरों को ₹ 5.30 करोड़ जारी (जनवरी 2015) किए। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने चार जिलों की नमूना जांच के आधार पर निम्नलिखित देखा:

<sup>17</sup> सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया का एक आनुवांशिक रूप है और मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के जनजातीय क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता अधिक है।

- ✓ खरगौन और शहडोल ने उनको दिए गये क्रमशः ₹ 41.65 लाख और ₹ 47.60 लाख के पूरे आवंटन को समर्पित कर दिया। संबंधित ए.सी.टी.डी. ने समर्पण का कारण एस.सी.ए. परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों और कार्य योजना का प्राप्त न होना बताया।
- ✓ धार जिले ने ₹ 71.40 लाख के आवंटन में से केवल ₹ 10.48 लाख का उपयोग किया, लेकिन एस.सी.ए. परीक्षण के लिये कोई शिविर आयोजित नहीं किया। इसके बजाय, सी.एम.एच.ओ., धार ने ₹ 9.94 लाख के एस.सी.ए. परीक्षण उपकरण खरीदे।
- ✓ यद्यपि सी.एम.एच.ओ., मण्डला ने ₹ 53.55 लाख की पूरी आवंटित निधि का उपयोग किया, तथापि नमूना जांच किये गये 19 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 10 में एस.सी.ए. परीक्षण आयोजित नहीं किए गए। यहां तक की एस.सी.ए. की स्थिति दर्शाते हुए कोई स्वास्थ्य कार्ड उन नौ आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में भी जारी नहीं किए गए थे जहां परीक्षण आयोजित किए गये थे। इस प्रकार, एस.सी.ए. परीक्षण के लिए शिविर आयोजित करने का उद्देश्य हासिल नहीं हुआ और ₹ 53.55 लाख का समस्त व्यय निष्फल था।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एस.सी.ए. परीक्षण फिर से आयोजित किये जाएंगे।

### अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग रहवासियों के मासिक स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित न होने के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकता है। जनजातीय कार्य विभाग शिविर आयोजित न करने के लिए और जहां शिविर आयोजित किए गये हैं वहां छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति दर्शाने वाला कार्ड जारी न किए जाने के लिए सम्बन्धित ए.सी.टी.डी./स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर सकता है।

### 2.1.9 निष्कर्षों का सारांश

- राज्य में एस.टी. के लिए गुणवत्तायुक्त आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित ई.एम.आर.एस. के लिए शिक्षकों की भर्ती में जनजातीय कार्य विभाग के कमजोर दृष्टिकोण और बुनियादी ढांचे के विकास में देरी के कारण निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। ई.एम.आर.एस. में विषयवार शिक्षकों की अनुपलब्धता ने शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों को प्रभावित किया।
- राज्य में स्थापित अन्य आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में भी बुनियादी ढांचे की कमी थी। बुनियादी ढांचे में आनुपातिक वृद्धि किए बिना छात्रावासों को उच्च संख्या के लिये उन्नयित किया गया था। निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियों के कारण इन आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के लिये उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। कलेक्टर आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रहने वाले रहवासियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित करने में असफल रहे।
- राज्य में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन के वित्तीय प्रबंधन में निर्धारित लेखा पुस्तकों का संधारण न होना, वार्षिक लेखाओं का बकाया रहना, भारत सरकार को अवास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, आठ से 15 वर्ष पहले जारी किए गये पता न लगाए जाने योग्य अग्रिमों और क्रय में प्रावधानों के उल्लंघन थे।
- ए.सी.टी.डी. और बी.ई.ओ. द्वारा आश्रम शालाओं/छात्रावासों के नियमित निरीक्षण में अत्यधिक कमी थी।

### 2.1.10 अनुशंसाओं का सारांश

- जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के अनिवार्य बही-खातों को संधारित करने और खातों को अंतिम रूप देने में विफलता की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विफलता जानबूझकर नहीं थी तथा दुरुपयोग और धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं थी, सतर्कता दृष्टिकोण से करनी चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को इस विफलता के लिए सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए तथा अविलंब उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए।
- भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के पदाधिकारियों पर उत्तरदायित्व तय करना चाहिए तथा उचित विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को सतर्कता दृष्टिकोण से लंबी अवधि से पड़े असमायोजित अग्रिम के मुद्दे की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दुरुपयोग या धोखाधड़ी नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग और मध्य प्रदेश शासन को अप्रयुक्त अग्रिमों को वापस/समायोजित करने में विफल होने के लिए जिला और सोसायटी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए। आयुक्त, आदिवासी विकास, जो सोसायटी के पदेन सचिव भी हैं, को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले समायोजन के लिए बकाया अग्रिमों की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को ई.एम.आर.एस. में प्राचार्यों/व्याख्याताओं/शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिये और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संविदा/अतिथि शिक्षकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को 247 छात्रावासों, जो दिसम्बर 2012 में उन्नयित किए गये थे, में तत्काल आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को प्रत्येक आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पालक समिति का गठन और वे प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं ये सुनिश्चित करना चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं हों।
- जनजातीय कार्य विभाग रहवासियों के मासिक स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित न होने के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकता है। जनजातीय कार्य विभाग शिविर आयोजित न करने के लिए और जहां शिविर आयोजित किए गये हैं वहां छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति दर्शाने वाला कार्ड जारी न किए जाने के लिए सम्बन्धित ए.सी.टी.डी./स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर सकता है।

## लेखापरीक्षा कंडिकाएं

### जनजातीय कार्य विभाग

#### 2.2 बैंक खाते का अनाधिकृत संचालन एवं ब्याज की हानि

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (स.आ.आदि.वि.), सिवनी ने अनाधिकृत रूप से बचत बैंक खाता खोला और बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए आदिवासी कल्याण योजना निधियों की राशि ₹ 112.51 करोड़ जमा किया। स.आ.आदि.वि., जमा धन पर ब्याज के क्रेडिट के लिए बैंक के साथ समय पर कार्रवाई करने में भी असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.44 करोड़ की हानि हुई।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड-I का नियम 6 निर्दिष्ट करता है कि वित्त विभाग की सहमति के बिना समेकित निधि तथा लोक लेखे से निवेश करने या अन्यत्र जमा करने हेतु राशि नहीं निकाली जा सकती है। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी (अक्टूबर 1998) किए थे कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए बैंक खाते बंद किए जाने चाहिए और शासकीय राशि, शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खंड-I (एम पी टी सी) का नियम 284 निर्दिष्ट करता है कि कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि उसका तत्काल वितरण अपेक्षित न हो। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना एक गम्भीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (स.आ.आदि.वि.), सिवनी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स.आ.आदि.वि. ने वित्त विभाग की अनुमति के बिना फरवरी 2007 में एक बचत खाता<sup>18</sup> खोला था। व्यय की प्रत्याशा में फरवरी 2007 से जुलाई 2016 के दौरान आदिवासी कल्याण योजना से संबंधित राशि ₹ 112.51 करोड़ कोषालय से आहरित कर इस बैंक खाते में जमा किए गए। इन जमा राशियों में से, राशि ₹ 7.06 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस अर्थात् संबंधित वर्षों के 31 मार्च को, इस खाते में जमा किए गए थे, जो स्पष्टतः इंगित करता है कि बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए ये राशियाँ कोषालय से आहरित की गई थी। इस प्रकार, स.आ.आदि.वि. ने बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए समेकित निधि से राशि आहरित करने संबंधी संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन किया।

आगे जांच में पाया गया कि बैंक ने इस बचत खाते में राशि ₹ 2.44 करोड़ का ब्याज मई 2007 से फरवरी 2015 के दौरान क्रेडिट किया था। यद्यपि, बैंक द्वारा ब्याज की ये प्रविष्टियाँ या तो उसी दिन या अधिकांशतः दो से तीन दिनों के भीतर स्वतः ही वापस ली गई। इस तथ्य के बावजूद कि स.आ.आदि.वि., बैंक द्वारा प्रदाय किए गए आवधिक बैंक खाता विवरण के माध्यम से ब्याज वापसी से अवगत था, स.आ.आदि.वि. द्वारा इस प्रकार ब्याज वापसी किये जाने के कारणों की जांच नहीं की गई।

उक्त पर लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर, बैंक ने विरोधाभासी उत्तर दिया। बैंक ने कहा (अप्रैल 2017 और मई 2017) कि स.आ.आदि.वि. ने बैंक को चालू खाता खोलने के लिए कहा था लेकिन मानवीय त्रुटि के कारण बैंक खाता बचत श्रेणी में खुल गया। बैंक के अनुसार, स.आ.आदि.वि. को इस त्रुटि के बारे में सूचित किया गया था, परन्तु उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसी खाता संख्या को जारी रखने का आग्रह किया क्योंकि मौजूदा खाता संख्या विभिन्न विभागों को भुगतानों एवं वितरण के उद्देश्यों हेतु सूचित

<sup>18</sup> बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिवनी में बचत बैंक खाता क्रमांक 20068246878

किया जा चुका था। इस प्रकार, बचत खाता जारी रखा गया था और अंतर्निहित सहमति के साथ-साथ विभाग के निर्देशों के अनुसार जमा ब्याज को वापस लिया गया था। यद्यपि, बैंक ने आश्चर्यजनक रूप से सूचित किया कि विभाग के मौखिक या लिखित निर्देशों के अभाव में जून 2015 से कोई ब्याज वापसी नहीं ली गई थी।

स.आ.आदि.वि., सिवनी ने अपने उत्तर (जून 2017) में बैंक के कथन का खंडन किया और कहा कि विभाग ने बचत खाते को चालू खाते में बदलने के लिए बैंक को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। साथ ही, बैंक, ब्याज प्रविष्टियों को वापस लेने के विभाग के निर्देश का पूर्व प्राधिकार पत्र को भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

इस पर लेखापरीक्षा में ध्यान इंगित किए जाने पर, स.आ.आदि.वि. ने पूर्व में ही वापस ली गई ब्याज प्रविष्टियों की राशि ₹ 2.44 करोड़ को वापस प्राप्त किये बिना ही जुलाई 2017 में खाता बंद कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण की जांच करने हेतु कलेक्टर (सिवनी) ने एक समिति भी (अगस्त 2017) गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष (सितम्बर 2017) दिया कि, स.आ.आदि.वि., बैंक के साथ ब्याज वापसी के मुद्दे को समय-समय पर उठाने में असफल रहा और बैंक के साथ सभी पत्र व्यवहार केवल लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण प्रतिवेदित किए जाने के बाद किए गए।

इस प्रकार, स.आ.आदि.वि. के बैंक के साथ समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप बचत खाते से वापस ली गई ब्याज प्रविष्टियों के कारण राशि ₹ 2.44 करोड़ की हानि हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) के दौरान प्रमुख सचिव, आदिवासी कार्य विभाग ने जवाब दिया कि बैंक से ब्याज की राशि वसूलने के लिए समय पर कार्रवाई करने हेतु स.आ.आदि.वि., सिवनी को निर्देश जारी किए गए थे।

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

### 2.3 निरर्थक व्यय

कोयला धारित क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुमति देने से पूर्व, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) की आपत्ति को संज्ञान में लेने में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सिंगरौली विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप कॉलोनी के विकास पर सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 1.95 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ क्योंकि बाद में भूमि को एन.सी.एल. द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि कोयला प्राप्त करने योग्य है तो वह सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके किसी भाग को अधिग्रहित करने की अपने आशय की सूचना आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा दे सकती है। कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि कोयला खदानों के सम्बन्ध में मालिकों के अधिकार, हक और हित सभी ऋणभारों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार को हस्तांतरित तथा पूर्णतः अधिकृत हो जाएंगे।

सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा ग्राम पंजरेह में खसरा क्रमांक 47/1 की 4.047 हेक्टेयर भूमि आवासीय उद्देश्य हेतु सिंगरौली विकास प्राधिकरण को आवंटित (अगस्त 2012) की गई थी। संयुक्त संचालक (जे.डी.), नगर तथा ग्राम निवेश (टी. एण्ड सी.पी.), रीवा द्वारा ग्राम पंजरेह में आवंटित 4.047 हेक्टेयर भूमि पर पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना के विकास हेतु विकास अनुज्ञा जारी (अक्टूबर 2012) की गई थी। तत्पश्चात, सिंगरौली विकास प्राधिकरण ने ग्राम पंजरेह के खसरा क्रमांक 47/1, 48/1, 49/1 तथा 50/1 पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत (अप्रैल 2014) की। जे.डी., टी. एण्ड सी.पी., सिंगरौली ने नवम्बर 2014 में पुनरीक्षित विकास अनुज्ञा जारी की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रारूप सिंगरौली विकास योजना 2031 अधिसूचित तथा प्रकाशित (फरवरी 2014) की तथा आपत्तियाँ/सुझावों को आमंत्रित किया। प्रारूप योजना के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार, ग्राम पंजरेह अन्य ग्रामों के साथ कोयला धारित क्षेत्र में आ रहा था। एन.सी.एल., सिंगरौली ने अपनी आपत्ति जे.डी., टी. एण्ड सी.पी., सिंगरौली को प्रस्तुत (मार्च 2014) की तथा कुछ खनन पट्टे वाले क्षेत्रों को सिंगरौली विकास योजना 2031 से बाहर रखने का अनुरोध किया। एन.सी.एल. की आपत्ति पंजरेह के क्षेत्र को सम्मिलित करती थी जिसमें पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना विकसित की जा रही थी। जे. डी., टी. एण्ड सी.पी. की अध्यक्षता वाली एक समिति ने प्रारूप सिंगरौली विकास योजना 2031 पर प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण किया जिससे निष्कर्ष निकला (अक्टूबर 2014) कि एन.सी.एल. की आपत्ति स्वीकार योग्य थी। आयुक्त-सह-संचालक, टी. एण्ड सी.पी. द्वारा भी समिति की अनुशंसा स्वीकार की गई थी।

तथापि, उसी जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. ने ग्राम पंजरेह में पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना की पुनरीक्षित विकास अनुज्ञा स्वीकृत (नवम्बर 2014) करते समय ग्राम पंजरेह के विकास पर एन.सी.एल. की आपत्ति का संज्ञान नहीं लिया। तत्पश्चात, भारत सरकार ने कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 की


धारा 4 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंजरेह में भूमि का अधिग्रहण अधिसूचित (मई 2016) किया तथा एन.सी.एल. ने सिंगरौली विकास प्राधिकरण को सूचित (मई 2016 एवं अक्टूबर 2016) किया कि ग्राम पंजरेह में कोयला खनन हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है जिससे इन भूमि पर विकास उपयोगी नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, सिंगरौली विकास प्राधिकरण ने पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना का विकास कार्य रोक दिया (जनवरी 2017) तथा एन.सी.एल. से क्षतिपूर्ति के रूप में योजना पर व्यय की गई राशि के भुगतान हेतु ₹ 2.94 करोड़ की माँग की। हालांकि, एन.सी.एल. ने इस प्रकार की माँग को यह कहते हुये (मार्च 2017) टुकरा दिया कि कोयला धारित क्षेत्र पर उनकी आपत्तियों को अनदेखा करते हुये अनुज्ञा प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. द्वारा नवम्बर 2014 में पुनरीक्षित विकास अनुज्ञा जारी करने के पश्चात सिंगरौली विकास प्राधिकरण ने पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना के विकास कार्यों पर ₹ 1.95 करोड़ व्यय किया। यदि जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. ने एन.सी.एल. की आपत्तियों, जो उनके द्वारा सिंगरौली विकास योजना 2031 हेतु आपत्तियों की सुनवाई के दौरान पहले ही स्वीकार की गई थीं (अक्टूबर 2014), की अनदेखी कर अनुज्ञा प्रदान करने की त्रुटि न की होती तो ₹ 1.95 करोड़ का निरर्थक व्यय टाला जा सकता था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर संचालक, टी. एण्ड सी.पी., भोपाल ने स्वीकार किया (मई 2018) कि जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. द्वारा प्रदान की गई पुनरीक्षित अनुज्ञा एक त्रुटि थी तथा यह उचित होता कि पुनरीक्षित अनुज्ञा सिंगरौली विकास योजना 2031 के प्रकाशन के पश्चात जारी की जाती।


प्रकरण अनुवर्ती अनुस्मारकों (अगस्त 2017, दिसम्बर 2017 तथा मार्च 2018) सहित शासन को प्रतिवेदित (जून 2017) किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2018)।

ग्वालियर  
दिनांक: 05 नवम्बर 2018

  
(राजीव कुमार पाण्डे)  
महालेखाकार  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)  
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 09 नवम्बर 2018

  
(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



---

---

परिशिष्ट

---

---

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भ: कडिका 2.1.2, पृष्ठ संख्या 8)

चयनित जिले, विकासखण्ड एवं आवासीय विद्यालय/ छात्रावास

चयनित जिला	चयनित विकासखण्ड	चयनित आवासीय विद्यालय/ छात्रावास	आवासीय विद्यालय/ छात्रावास के प्रकार
धार	धरमपुरी	एस.टी. बालक आश्रम शाला अंग्रेजी माध्यम धरमपुरी	आश्रम शाला
		एस.टी. कन्या आश्रम शाला, भावन्या	आश्रम शाला
		एस.टी. बालक उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र, धरमपुरी	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. कन्या उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र, धरमपुरी	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, धरमपुरी	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
		कन्या शिक्षा परिसर, धरमपुरी	के.एस.पी.
	कुक्षी	एस.टी. बालक आश्रम शाला, डेहरी	आश्रम शाला
		एस.टी. कन्या आश्रम शाला, ढोल्या	आश्रम शाला
		एस.टी. प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, कुक्षी	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, ढोल्या	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, कुक्षी	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
		ई.एम.आर.एस. कुक्षी	ई.एम.आर.एस.
		नेहरू आश्रम तलावड़ी, कुक्षी	सहायता प्राप्त एन.जी. ओ. आवासीय विद्यालय
	सरदारपुर	एस.टी. बालक आश्रम शाला अंग्रेजी माध्यम, सरदारपुर	आश्रम शाला
		एस.टी. कन्या आश्रम शाला, अमझोरा	आश्रम शाला
		एस.टी. बालक उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र, सरदारपुर	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. कन्या उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र, सरदारपुर	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, सरदारपुर	पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास
		ई.एम.आर.एस., धार विकासखण्ड धार	ई.एम.आर.एस.
खरगोन	भगवानपुरा	एस.टी. कन्या आश्रम शाला, सिरवेल	आश्रम शाला
		एस.टी. बालक आश्रम शाला, काबरी	आश्रम शाला
		प्री-मैट्रिक उत्कृष्ट एस.टी. बालक छात्रावास	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		प्री-मैट्रिक उत्कृष्ट एस.टी. कन्या छात्रावास	प्री-मैट्रिक छात्रावास
	खरगौन	एस.टी. कन्या आश्रम शाला, ऊन	आश्रम शाला
		एस.टी. बालक आश्रम शाला, बेजापुरा	आश्रम शाला
		प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, खरगौन	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		प्री-मैट्रिक एस.टी. कन्या छात्रावास, खरगौन	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		पोस्ट मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, खरगौन	पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास
		पोस्ट मैट्रिक एस.टी. कन्या छात्रावास, खरगौन	पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास
		कन्या शिक्षा परिसर, खरगौन	के.एस.पी.
		कन्या आश्रम शाला, आदिवासी विकास केन्द्र,	सहायता प्राप्त एन.जी.

चयनित जिला	चयनित विकासखण्ड	चयनित आवासीय विद्यालय/ छात्रावास	आवासीय विद्यालय/ छात्रावास के प्रकार
		बबलई	ओ. आवासीय विद्यालय
		ई.एम.आर.एस., खरगौन	ई.एम.आर.एस.
मण्डला	बिछिया	एस.टी. बालक आश्रम शाला, रामनगर	आश्रम शाला
		एस.टी. अंग्रेजी माध्यम कन्या आश्रम शाला, बिछिया	आश्रम शाला
		प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, सिझौरा	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, बिछिया	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		पोस्ट-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, बिछिया	पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास
		ई.एम.आर.एस., सिझौरा	ई.एम.आर.एस.
	मण्डला	एस.टी. कन्या आश्रम शाला, महाराजपुर	आश्रम शाला
		एस.टी. बालक आश्रम शाला, प्रेमपुर	आश्रम शाला
		प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, मण्डला	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		प्री-मैट्रिक एस.टी. कन्या छात्रावास, मण्डला	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		पोस्ट मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, मण्डला	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
		पोस्ट मैट्रिक एस.टी. कन्या छात्रावास, मण्डला	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
		कन्या शिक्षा परिसर, मण्डला	के.एस.पी.
		ई.एम.आर.एस., मण्डला	ई.एम.आर.एस.
		वनवासी सेवा मण्डल कुमार छात्रावास, महाराजपुर	सहायता प्राप्त एन.जी. ओ. छात्रावास
	नारायणगंज	एस.टी. बालक आश्रम शाला, कापा	आश्रम शाला
		एस.टी. अंग्रेजी माध्यम कन्या आश्रम शाला	आश्रम शाला
		प्री-मैट्रिक उत्कृष्ट एस.टी. कन्या छात्रावास	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		प्री-मैट्रिक उत्कृष्ट एस.टी. बालक छात्रावास	प्री-मैट्रिक छात्रावास
शहडोल	सोहागपुर	एस.टी. अंग्रेजी माध्यम कन्या आश्रम शाला, शहडोल	आश्रम शाला
		एस.टी. बालक आश्रम शाला, कुदराटोला, धुरवार, शहडोल	आश्रम शाला
		एस.टी. प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, शहडोल	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, शहडोल	प्री-मैट्रिक छात्रावास
		एस.टी. पोस्ट-मैट्रिक बालक छात्रावास, शहडोल	पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास
		कन्या शिक्षा परिसर, शहडोल	के.एस.पी.
		ई.एम.आर.एस., धुरवार	ई.एम.आर.एस.
		आवासीय कन्या उ.मा.वि., जयसिंहनगर विकासखण्ड जयसिंहनगर	सहायता प्राप्त एन.जी. ओ. आवासीय विद्यालय

## परिशिष्ट 2.1.2

(सन्दर्भ: कडिका 2.1.4.1, पृष्ठ संख्या 12)

ई.एम.आर.एस. में स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

स. क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे जाने वाले पद*	कार्यरत स्थिति		रिक्त पद
				नियमित	संविदा	
1.	प्राचार्य	29	29	9	0	15**
2.	व्याख्याता (पी.जी.टी.)	290	120	0	25	95
3.	शिक्षक (टी.जी.टी.)	261	180	0	28	152
4.	शिक्षक (संगीत)	29	27	0	01	26
5.	शिक्षक (शिल्पकला)	29	29	0	0	29
6.	शिक्षक (तबला)	08	08	0	0	08
7.	सहायक शिक्षक (विज्ञान)	63	58	0	0	58
8.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	29	29	0	0	29
9.	सहायक शिक्षक	53	53	0	0	53

(स्रोत: सोसायटी के अभिलेख)

\* स्वीकृत पदों और भरे जाने वाले पदों में अंतर था क्योंकि कुछ विद्यालय नये थे और वहां प्राचार्य/शिक्षकों के पूर्ण पदों की आवश्यकता नहीं थी।

\*\* शेष पांच पद प्रभारी प्राचार्य के द्वारा प्रबंधित थे क्योंकि ये विद्यालय 2016-17 में खुले थे।

परिशिष्ट 2.1.3

(सन्दर्भ: कंडिका 2.1.4.3, पृष्ठ संख्या 15)

नमूना जांच किये गये ई.एम.आर.एस. में जिला स्तरीय समिति की बैठकें

जिले का नाम	ई.एम.आर.एस. का नाम	आरंभ वर्ष	2012-17 के दौरान निर्धारित तिमाही बैठकों की संख्या	2012-17 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कमी
धार	कुक्षी	2006-07	20	0	20
धार	धार	2015-16	8	0	8
खरगौन	खरगौन	2016-17	4	3	1
मण्डला	मण्डला	2016-17	4	0	4
मण्डला	सिझौरा	2005-06	20	4	16
शहडोल	शहडोल	2011-12	20	5	15
योग			76	12	64

(स्रोत: नमूना जांच किये गये ई.एम.आर.एस. के अभिलेख)

**परिशिष्ट 2.1.4**  
(संदर्भ: कंडिका 2.1.7.1, पृष्ठ संख्या 23)  
मध्य प्रदेश क्रय नियम के अनुपालन बिना किए गए क्रय

स. क्रं.	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम	चयनित संस्था का नाम	क्रय सामग्री का विवरण (₹ लाख में)		
				वर्ष	सामग्री	व्यय
1.	धार	धरमपुरी	बालक आश्रम शाला (अंग्रेजी माध्यम), धरमपुरी	2014-15	वाटर कूलर, टैंक आदि	0.81
2.	धार	कुक्षी	बालक आश्रम शाला, डेहरी	2014-17	फर्नीचर, डायनिंग टेबल आदि	1.76
3.	धार	कुक्षी	कन्या आश्रम शाला, ढोल्या	2014-17	अलमारी, वाटर फिल्टर आदि	2.65
4.	धार	कुक्षी	प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, कुक्षी	2015-17	अलमारी, फर्नीचर आदि	1.47
5.	धार	कुक्षी	प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, ढोल्या	2014-17	अलमारी, बर्तन आदि	1.91
6.	धार	कुक्षी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कुक्षी	2014-15	यूनीफॉर्म	11.58
7.	धार	सरदारपुर	बालक आश्रम शाला (अंग्रेजी माध्यम), सरदारपुर	2015-16	बर्तन, कुर्सी आदि	0.33
8.	खरगौन	भगवानपुरा	एस.टी. कन्या आश्रम शाला, सिरवेल	2015-16	लोहे की चारपाई, बर्तन	5.56
9.	खरगौन	भगवानपुरा	एस.टी. बालक आश्रम शाला, काबरी	2015-16	लोहे की चारपाई, बर्तन	2.16
10.	खरगौन	भगवानपुरा	प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक उत्कृष्ट छात्रावास, भगवानपुरा	2014-15	लोहे की चारपाई	2.00
11.	खरगौन	भगवानपुरा	प्री-मैट्रिक एस.टी. कन्या उत्कृष्ट छात्रावास, भगवानपुरा	2016-17	लोहे की चारपाई, बर्तन	1.63
12.	खरगौन	खरगौन	एस.टी. कन्या आश्रम शाला, ऊन	2016-17	लोहे की चारपाई, बर्तन	1.60
13.	खरगौन	खरगौन	एस.टी. बालक आश्रम शाला, बेजापुरा	2016-17	लोहे की चारपाई, बर्तन	2.44
14.	खरगौन	खरगौन	प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, खरगौन	2016-17	लोहे की चारपाई, बर्तन	2.55
15.	खरगौन	खरगौन	प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, खरगौन	2016-17	बर्तन	1.60
16.	खरगौन	खरगौन	पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, खरगौन	2016-17	लोहे की चारपाई, बर्तन	1.33
17.	मण्डला	बिछिया	एस.टी. बालक आश्रम शाला, रामनगर	2015-16	बेडशीट, चारपाई	3.18

स. क्र.	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम	चयनित संस्था का नाम	कय सामग्री का विवरण (₹ लाख में)		
				वर्ष	सामग्री	व्यय
18.	मण्डला	बिछिया	एस.टी. अंग्रेजी माध्यम कन्या आश्रम शाला, बिछिया	2015-17	डायनिंग टेबल, बर्तन	3.98
19.	मण्डला	बिछिया	प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, सिझौरा	2015-17	डायनिंग टेबल, बर्तन	4.83
20.	मण्डला	बिछिया	प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, बिछिया	2015-17	डायनिंग टेबल, कम्बल	5.84
21.	मण्डला	बिछिया	पोस्ट-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, बिछिया	2015-17	डायनिंग टेबल, कम्बल	7.99
22.	मण्डला	बिछिया	ई.एम.आर.एस., सिझौरा	2012-16	कम्प्यूटर, खेल सामग्री, लेखन सामग्री	49.55
23.	मण्डला	मण्डला	एस.टी. बालक आश्रम शाला, प्रेमपुर	2016-17	डायनिंग टेबल, तकिया	1.18
24.	मण्डला	मण्डला	प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, मण्डला	2015-17	बर्तन, चारपाई	1.30
25.	मण्डला	मण्डला	प्री-मैट्रिक एस.टी. कन्या छात्रावास, मण्डला	2015-17	चारपाई, बर्तन	2.55
26.	मण्डला	मण्डला	पोस्ट मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, मण्डला	2015-17	चारपाई, बर्तन	2.49
27.	मण्डला	मण्डला	पोस्ट मैट्रिक एस.टी. कन्या छात्रावास, मण्डला	2016-17	गद्दा, पंखा	3.62
28.	मण्डला	मण्डला	कन्या शिक्षा परिसर, मण्डला	2016-17	चारपाई, बर्तन	1.64
29.	मण्डला	नारायणगंज	एस.टी. बालक आश्रम शाला, कापा	2016-17	डायनिंग टेबल, तकिया	3.42
30.	मण्डला	नारायणगंज	प्री-मैट्रिक उत्कृष्ट एस.टी. कन्या छात्रावास	2015-17	चारपाई, बर्तन	1.89
31.	मण्डला	नारायणगंज	प्री-मैट्रिक उत्कृष्ट एस.टी. बालक छात्रावास	2015-17	चारपाई, डायनिंग टेबल	1.93
32.	शहडोल	सोहागपुर	प्री-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, शहडोल	2016-17	बर्तन, खेल सामग्री	0.79
33.	शहडोल	सोहागपुर	प्री-मैट्रिक एस.टी. कन्या छात्रावास, शहडोल	2016-17	प्रवर्धक, माईक सेट	1.10
34.	शहडोल	सोहागपुर	पोस्ट-मैट्रिक एस.टी. बालक छात्रावास, शहडोल	2016-17	बर्तन, खेल सामग्री	1.07
<b>योग</b>						<b>139.73</b>

(स्रोत: नमूना जांच किये गये आवासीय विद्यालयों / छात्रावासों के अभिलेख)

©  
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in)